प्रकाशन का 42 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 42 अंक – 31 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 31 – 07 अगस्त 2017 मूल्य पांच रूपए

शिंदे के फरमान के बाद वीरभद्र विरोधीयों की रणनीति पर लगी निगाहें

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस का प्रभार संभालने के बाद अपनी पहली पत्रकार वार्ता में सुशील कुमार शिन्दे ने यह दावा किया है कि इस समय न तो सरकार के नेतृत्व में परिवर्तन होगा ओर न ही संगठन के। शिन्दे के प्रभार संभालने से कांग्रेस सरकार और संगठन में चल रहे मदभेद इस सीमा तक पहुंच गये थे कि कांग्रेस के छ: विधायकों द्वारा मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ एक पत्र कांग्रेस हाईकमान को भेज दिया था। कांग्रेस हाईकमान को पत्र भेजने के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष को भी इसकी अधिकारिक सूचना दे दी गयी थी और इसकी पुष्टि मीडिया को स्वयं सुक्खु ने की थी। यही नही इस पत्र की चर्चा बाहर आने के बाद परिवहन मन्त्री जीएसबाली ने अपने जन्मदिन पर कांगड़ा में पहले की ही तरह एकआयोजन रखा था। इस अवसर पर कांग्रेस के कई नेता और मंत्री तक पहुंचे थे। सुक्खु दिल्ली से सीधे इसके लिये कांगड़ा पहुंचे थे इस आयोजन को मीडिया ने वीरभद्र विरोधीयों का शक्ति प्रदर्शन करार दे दिया था और मीडिया के ऐसे चित्रण पर किसी ने भी इसका खण्डन तक नही किया बल्कि बाली के इस आयोजन के बाद प्रदेश के राजनीतिक हल्कों में तो यहां तक चर्चा फैल गयी कि बाली और उनके साथी विधायक कभी भी भाजपा का दामन थामने की घोषणा कर सकते हैं।

लेकिन अब जब पत्रकार वार्ता में शिंदे से पार्टी के विधायकों द्वारा ऐसा पत्र लिखे जाने के बारे में पुछा गया तो उन्होने इससे स्पष्ट इन्कार कर दिया यहां तक कह दिया कि स्वयं सुक्खु कीओर से भी उन्हे ऐसे पत्र की जानकारी नही दी गयी है। जब शिंदे ने यह इन्कार किया तो सुक्खु उनकी बगल में ही बैठे थे और वह इस पर आज एकदम खामोश बैठे रहे। जिस पार्टी अध्यक्ष ने स्वयं ऐसा पत्र लिखवा जाना मीडिया में स्वीकारा हो आज उसी के सामने प्रभारी द्वारा उसे एक तरह से सिरे से खारिज कर देना अध्यक्ष की विश्वसनीयता पर सवाल खडे कर जाता है। कल मीडिया सुक्खु के किसी भी कथन पर आसानी से विश्वास नही कर पायेगा और सार्वजनिक जीवन में यह विश्वनीयता ही सबसे बड़ा हथियार होती है। सुक्खु ने विधायकों के इस कथित पत्र को यह कह कर सार्वजनिक नही किया था कि इससे विधायको के साथ विश्वासघात होगा।अब जिन विधायकों के लिये सुक्खु ने प्रभारी के हाथों अपनी यह फजीहत झेली है वह विधायक और सुक्खु जनता में अपनी विश्वनीयता बहाल करने के लिये क्या कदम उठायेंगे। क्योंकि जब वीरभद्र

समर्थकों ने विधायकों का एक पत्र हाईकमान को देकर सुक्खु को हटाने की मांग की थी तब 24 विधायकों ने सुक्खु के समर्थन में पत्र लिखकर अध्यक्ष में अपना विश्वास व्यक्त किया था।

जब मनकोटिया को पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष पद से बर्खास्त किया गया था और मनकोटिया ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में खुलकर वीरभद्र के खिलाफ हमला बोला था तब बाली ही एक मात्र ऐसे मंत्री थे जो मनकोटिया के साथ खड़े दिखे थे। फिर वीरभद्र ने भी मनकोटिया – बाली के गठजोड़ पर खुलकर कटाक्ष किया था। बाली के केन्द्र में कुछ भाजपा मन्त्रीयों के साथ अच्छे रिश्ते और उनके साथ अवसर होती रही बैठकें भी प्रशासनिक और राजनीतिक हल्को में किसी से छुपी नही रही हैं। चौधरी वीरेन्द्र सिंह से तो कांग्रेस के समय से उनके रिश्ते बहुत निकटता के रहे हैं जो आज तक कायम हैं। संभवत: इन्ही रिश्तो के कारण बाली को लेकर यह फैल चुका है कि बाली देर सवेर चुनावों से पहले भाजपा में जायेंगे ही। बाली को लेकर बन रही इन धारणाओं को विराम लगाने का भी कोई प्रयास सामने नही आया है। हालांकि अब शिंदे बाली के घर भी जा आये हैं। शिंदे को प्रभारी के नाते प्रदेश कांग्रेस में एक जुटता बनाये रखना जहां पहली राजनीतिक आवश्यकता है वहीं पर यह प्रबन्ध करना भी उतना ही आवश्यक होगा कि सरकार और स्वयं मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ लगने वाले आरोप कम से कम बाहर आयें। लेकिन इस दिशा में जब शिंदे ने मनकोटिया के खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई किये जाने का संकेत दे दिया है तब लगता है कि इस संद्धर्भ में शिंदे के सामने भी अभी तक सही तस्वीर नही आ पायी है।

वीरभद्र पिछले दिनों यह सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि उनके ऊपर हो रहे भाजपा के हमलों में संगठन की ओर से कोई भी उनके बचाव में नही आ रहा है। भाजपा ने कानून व्यवस्था और मुख्यमन्त्री पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को ही चुनाव का केन्द्रिय मुद्दा बनाने की रणनीति बना रखी है। बल्कि विधानसभा के मानसून सत्र में भी इन्ही मुद्दों पर सरकार को घेरा जायेगा। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि शिंदे के प्रभार संभालने के बाद कौन – कौन मुख्यमन्त्री के बचाव में आता है और भाजपा पर भी उसी तर्ज में हमला कर पाता है। क्योंकि यदि कांग्रेस मनकोटिया के खिलाफ कारवाई करती है तो मनकोटिया के हमले और तेज हो जायेंगे और वह सब पर भारी पड़ जायेगा।

क्या चुनावी हार की आशंका से लाया गया था ये प्रस्ताव उठने लगा है ये स्वाल

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार पूर्व मुख्यमन्त्रीयों को कुछ सुविधाएं देने का प्रस्ताव लायी थी। मन्त्री परिषद की बैठक में सामान्य विभाग की ओर से लाये गये प्रस्ताव के अनुसार पूर्व मुख्यमन्त्रीयों से अब एक नियमित डाक्टर और काफिले में डाक्टर मुक्त एंबुलैन्स ड्राईवर सहित एक एस यू वी गाडी पंसद के दो सुरक्षा अधिकारी एवम लैण्ड लाईन और मोबाईल के लिये प्रतिवर्ष 50 हजार तथा प्रशासनिक खर्च के लिये एक लाख रूपये प्रतिवर्ष देने जा रही थी। इस आश्य का प्रस्ताव मन्त्री परिषद में लाया गया। लेकिन जब इसके राजनीतिक प्रभाव की ओर कुछ मन्त्रियों ने ध्यान आर्किषत किया तो इसे वापिस ले लिया गया। मन्त्रियों का तर्क था कि अब तीन माह बाद प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं ऐसे में इस फैसले को लेकर पार्टी की चुनावी संभावनाओं के बारे में लोगों में नकारात्मक संदेश जायेगा इसलिये ऐसा फैसला नही लिया जाना चाहिये।

सरकारऔर पार्टी सत्ता में न केवल वापसी बल्कि वीरभद्र को सातंवी बार मुख्यमन्त्री बनाने के दावे करती आ रही है। पार्टी के नये प्रभारी शिंदे ने वीरभद्र और सुक्खु के बीच चल रहे टकराव को विराम देने के लिये अनुशासन का चाबुक चलाकर सबको एकजुट रहने की नसीहत देते हुए यहां तक ऐलान कर दिया कि न तो सुक्खु हटेंगे और न ही वीरभद्र। बल्कि कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सुक्खु को हटाने के लिये लगाये गये नारों का कड़ा संज्ञान लेते हुए वीरभद्र के बेटे और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह से भी मंच से यह ऐलान करवाया कि भविष्य में प्रदेश अध्यक्ष की राय से ही हर फैसला लेंगे और उन्हे पूरा सहयोग देंगे। यह माना जा रहा है कि यदि आने वाले विधानसभा चुनावों में ईमानदारी से पार्टी एक जुटता के साथ काम करेगी तो वह भाजपा को कड़ी चुनौती पेश कर सकती है।

लेकिन इस समय कार्यकाल के अन्तिम दिनों में पूर्व मुख्यमन्त्रीयों को यह सुविधायें देने का प्रयास किया गया उससे अनचाह ही यह संदेश चला गया कि वीरभद्र और उनके सचिवालय ने अभी से स्वीकार कर लिया है कि चुनावों में उनकी हार होने जा रही है। मन्त्री परिषद में यह प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से लाया गया और सामान्य प्रशासन विभाग स्वयं मुख्यमन्त्री के पास है। फिर मन्त्री परिषद के सचिव की जिम्मेदारी मुख्य सचिव के पास होती है। ऐसे में सामन्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार किया गया यह प्रस्ताव मन्त्री परिषद के ऐजेंण्डा में डालने से पूर्व इसे मुख्य सचिव और मुख्यमन्त्री द्वारा अवश्य देखा गया होगा क्योंकि हर मन्त्री अपने विभाग से संबधित ऐजेण्डे को स्वयं मन्त्री परिषद में रखता है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि यह प्रस्ताव तैयार करने से पहले इससे जुड़े अधिकारी राजनीतिक आकंलन करने में या तो एकदम असफल रहे हैं या फिर उन्होने जानबूझकर अपने राजनीतिक विरोधीयों को एक मुद्दा और थमा दिया। बल्कि इससे यह आशंकाऔर बन गयी है कि लोग चुनाव आते – आते एकाध ऐसा और कारनामा कर सकते हैं।

शैल समाचार के नियमित पाठक बनने हेतू
विज्ञापन देने के लिये इन नम्बरों पर संपर्क करें

कार्यालय दूरभाष – 0177 – 2805015, **मो.** 8988587014, **मो.** 9418069978, **मो.** 9418020312
ई मेल – shailsamachar@gmail.com, **वेबसाईट –** www.shailsamachar.co.in

पाठकों की प्रतिक्रियाओं को भी विशेष स्थान दिया जायेगा
– संपादक

68वें वन महोत्सव पर राज्यपाल ने किया पौधारोपण

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि पौधारोपण के साथ उसकी जीवंतता को सुनिश्चित बनाना अधिक आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पौधा लगाने के बाद उसका जीवित न रहना भ्रूण हत्या के समान है। इसलिए, यह हम सबका नैतिक कर्त्तव्य है कि उसकी जीवंतता को सुनिश्चित बनाया जाए।

राज्यपाल वन विभाग तथा राज्य रेडक्रास के सहयोग से शिमला के निकट मशोबरा स्थित भागी जुब्बड़ में आयोजित 68वें वन महोत्सव के शुभारम्भ अवसर पर बोल रहे थे। राज्यपाल ने स्कूली बच्चों के साथ पौधारोपण किया। इस मौके पर लेडी गवर्नर दर्शना देवी भी उपस्थित थी। उन्होंने भी देवदार का पौधा रोपा।

राज्यपाल ने प्रदेश के हरित आवरण को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पौधारोपण सुखद भविष्य का आधार है। पांच तत्वों से बने इस शरीर को वायु के रूप में ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है। इसलिए ये जीवनदायी कहलाते हैं। लेकिन, जिस तरह पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और पेड़ कट रहे हैं वह चिंता का विषय है। ओजोन की परत कमजोर हो रही है और अल्ट्रावायलेट किरणें नुकसान पहुंचा रही हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं और वैज्ञानिक समय-समय पर इसके लिए आगाह कर रहे हैं। मानव भौतिक सुख की चाह में पर्यावरण को पीछे छोड़ता जा रहा है।

राज्यपाल ने कहा कि ऋषि-मुनियों ने हवन के रूप में वैज्ञानिक विधि दी ताकि पर्यावरण शुद्ध हो सके। वेदों में पौधारोपण को यज्ञ के समान ही कहा गया है। इसलिए, हमारा यह कर्तव्य बनता है कि अधिक से अधिक पौधा रोपण करें और उनका संवर्द्धन भी करें।

आचार्य देवव्रत ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि प्रदेश का हरित आवरण तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें और वृद्धि की जानी चाहिए। उन्होंने इस तरह के अधिक कार्यक्रम आयोजित करने पर बल देते हुए कहा कि इस अभियान से स्कूली बच्चों को जोड़ना चाहिए और उन्हें इसके महत्व को भी बताया जाना चाहिए।

उन्होंने राज्य रेडक्रास तथा वन विभाग द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और कहा कि वह इस अभियान से जुड़े हैं और ऐसे हर कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित बनाने के लिये तत्पर रहते हैं।

इस अवसर पर, राज्य रेडक्रास अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने राज्यपाल का पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेकर सभी को प्रोत्साहित करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह एक धार्मिक कार्य ही नहीं, बल्कि भावी पीढ़ी की सुरक्षा से भी जुड़ा है। उन्होंने कहा कि रेडक्रास समाज सेवा के विभिन्न कार्यों के साथ-साथ पौधारोपण अभियान को भी संचालित करती है। उन्होंने बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के साथ-साथ नशामुक्ति जैसे अभियानों को भी बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने जागरूक समाज के निर्माण में सहयोग की अपील की।

इस मौके पर, विक्ट्री इण्डिया नेशनल ऑरगेनाईजेशन ने राज्यपाल को राष्ट्रीय ध्वज भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर, देवदार और बान के लगभग 500 पौधे रोपे गए।

प्रधान मुख्य अरण्यपाल एस. के शर्मा, राज्य रेडक्रास के सचिव पी.एस राणा, राज्य रेडक्रास कार्यकारिणी के सदस्य, जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी, भागी जुब्बड़ (मशोबरा) के प्रधान विक्रम सिंह, स्कूली बच्चे तथा क्षेत्र के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी पौधारोपण अभियान में शामिल हुए।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
" NOTICE INVITING TENDER"

Sealed item rate tenders are hereby invited/re-invited on form No 6 & 8 by the Executive Engineer, HPPWD Division Barsar on behalf of Governor of H.P for the following works from the approved and eligible contractors/firms enlisted in H.P.P.W.D. in the appropriate class so as to reach in this office on or before **06-09-2017 to 10.30 A.M.** and will be opened on the same day at **11.00 A.M.** in the presence of intending contractors or their authorized representative. The tender form can be had from this office against cash payment [Non Refundable] on **05-09-2017 up to 4.00 PM.** The offer of the tender shall be kept open for 120 days.

Name of work No. 1:- C/O link road Uled to Dhamani via ChoaKhansara km. 0/0 to 5/540 (Sh:- P/L Soling from km. 1/220 to 1/855 & 4/155 to 5/540) Under MMGSY Estimated Cost:- 6,87,625/-Earnest Money :- 13,800/- Time :-Two Month Cost of form:-350/-

Name of work No. 2:- C/O link road Uled to Dhamani via ChoaKhansara km. 0/0 to 5/540 (Sh:- P/L wearing at rd. 1/0 to 1/855,4/155 to 5/540 & C/O 900mm dia RCC hume pipe culvert at rd. 1/600) Under MMGSY Estimated Cost:- 6,45,731/-Earnest Money :- 13,000/- Time :-Two Month Cost of form:-350/-

TERMS AND CONDITIONS

No.1:- The Earnest Money in the shape of National saving certificates /Time deposit Accounts/Saving Account/ FDRs in any of the post office/ Nationalized Bank in duly pledged in favour of the Executive Engineer Barsar must be accompanied with the application.

NO.2:- Conditional tenders and the tenders received without earnest money will out- rightly be rejected.

NO.3:- The contractor shall accompany his enlistment/ renewal order with his application for obtaining the tender documents.

No.4:- Executive Engineer Reserves the right to reject the tender without assigning any reason.

NO.5:- The work will be completed by the contractor within the stipulated period

No.6:- Tender forms will not be issued to those contractors who are not registered under HPGST Act-1988 /GST & photo copy of individual PAN No. allotted to them attached with their application at the time of applying for tender documents. Application will not be entertained without aforesaid documents.

NO.7:- The contractor /firms are required to insert the rate of each item in words as well as in figures failing which Executive Engineer reserves the right to accept / rejects any overall tender.

NO.8:- The tender shall be issued to only those contractors/firms who are found eligible suitable and competent.

No.9:- The tender forms shall be issued to eligible contractor depending upon their past performance and work experience which shall be duly evaluated by the technical evaluation committee.

No. 10:- The Tender forms of soling ,wearing and tarring shall be issued only to those contractors who will produce proper documents of ownership of required machinery and completion certificate of similar work issued by the concerned Executive Engineer also required.

No. 11:-contractor /firm having necessary documents past adequate experience shall be preferred.

No. 12:- Contractor who have failed to start /complete the work in hand with in reasonable time shall not be issued tender forms.

No.13:- One contractor should not have more than two major works in hand at a time.

NO.14:- If **06-09-2017** happens to be holiday the tender shall be opened on next working day at 11.00 A.M.

Adv. No.- 1962/17-18 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

मुख्यमंत्री ने दी 'हिमाचल निर्माता' को श्रद्धांजलि

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल निर्माता डॉ. वाई.एस. परमार को याद करते हुए कहा कि डॉ. परमार प्रख्यात राजनेता होने के अलावा एक महान दूरदर्शी तथा गतिशील नेता थे, जिन्होंने लोगों के विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर किया। उन्होंने यह बात शिमला के ऐतिहासिक रिज पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. वाई.एस. परमार की 111वीं जयन्ती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कही। उन्होंने इसके उपरांत विधानसभा में डॉ. परमार की जयंती मनाने के लिए आयोजित समारोह में भी शिरकत की।

मुख्यमंत्री के साथ राज्य कांग्रेस पार्टी मामलें प्रभारी सुशील कुमार शिंदे, बिहार के सुपॉल से सांसद व हिमाचल कांग्रेस समिति की सह-प्रभारी रंजीत रंजन, एआईसीसी सचिव आशा कुमारी, मंत्रिमण्डल सहयोगी, मुख्य संसदीय सचिव, सत्ता एवं विपक्ष के विधायक, विभिन्न बोर्डों व निगमों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के अतिरिक्त राज्य सरकार के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

हिमालयन पर्यटन सर्किट के लिए 100 करोड़ की परियोजना स्वीकृत:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। 'हिमालयन पर्यटन सर्किट' के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे राज्य में पर्यटन से जुड़ी 14 परियोजनाओं को विकसित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड की 9वीं बैठक में दी गई। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की।

सर्किट के अन्तर्गत चिन्हित की गई परियोजनाओं में क्यारीघाट में सैलानियों को सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त 25 करोड़ रुपये की लागत का सम्मेलन केन्द्र, संजौली-ढली वाईपास के समीप 7 करोड़ रुपये के हेलिपोर्ट का निर्माण कार्य, डल झील के सौंदर्यीकरण सहित कांगड़ा 'विलेज हार्ट' प्रत्येक के लिए चार करोड़ रुपये, तीन करोड़ रुपये की लागत से मनाली में अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों पर 'निःशुल्क क्लाईबिंग-स्टेंडिंग वॉल तथा सौरव कालिया वन विहार के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान व शिमला के सुन्नी में जलक्रीड़ा सुविधाओं को विकसित करना शामिल है।

शिमला के एक पहाड़ी पठार पर बनने वाले हेलिपोर्ट में इंडोर व आउटडोर निर्गमन के अलावा निजी हेलिकाप्टरों के उतरने की सुविधा भी होगी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि रज्जू मार्गो के निर्माण के उपरांत हिमाचल प्रदेश धार्मिक तथा साहसिक पर्यटन के लिए वैश्विक स्तर का पसंदीदा पर्यटक गंतव्य होगा। उन्होंने कहा कि राज्य पर्यटन में नए आयाम जोड़े गए हैं, जो आने वाले समय में न केवल पर्यटन उद्योग की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, बल्कि राज्य के लिए रोजगार व राजस्व सृजन के साधन भी होंगे।

बैठक में अवगत करवाया गया कि 'बिल्ट-ऑपरेट-ट्रांसफर' (बीओटी) आधार पर चार रज्जू मार्ग परियोजनाओं के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन परियोजनाओं में 150 करोड़ रुपये की धर्मशाला-मैकेलोड़गंज, 289 करोड़ रुपये की आदी-हिमानी -चामुंडा, 340 करोड़ रुपये की पलचान -रोहतांग तथा लगभग 94 करोड़ रुपये की भुंतर -बिजली-महादेव शामिल हैं, जो राज्य में साहसिक तथा धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करेगी।

मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि किन्नौर जिला को जोड़ते हुए सराहन से बशाल-कंडा रज्जू मार्ग परियोजना, भरमौर से भरमाणी माता, बिलासपुर में टोबा से श्री नैनादेवी जी तथा हमीरपुर में शाहतलाई से दियोटसिद्ध रज्जू मार्ग परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया की अवस्था में है।

मुख्यमंत्री ने मण्डी के महामृत्युंजय मंदिर परिसर से होर्डिंग्स व पोस्टरों को हटाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व में अतिक्रमण को हटाया गया था और अब बड़े-बड़े पोस्टरों व होर्डिंग्स से मंदिर परिसर घिरा हुआ है, जिन्हें तुरंत हटाने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने बेंटनी कैसल के पुनरूद्धार व नवीनीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुराने भवन को राज्य के सभी जिलों का इतिहास व संस्कृति को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से संग्रहालय के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

मुख्य सचिव वी.सी. फारका ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अनुरूप चम्बा के भलेई माता मंदिर में लिफ्ट के लिए 40 लाख रुपये की राशि, किन्नौर जिला के कल्पा में नारायण-नागिन मंदिर के निर्माण के लिए 50 लाख रुपये, स्पीलो में पार्किंग के लिए 48 लाख रुपये तथा शिमला जिला के सरपाड़ा में नाऊ-नाग झील के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए 25 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्किंग, मंदिरों के सौंदर्यीकरण तथा सार्वजनिक स्थलों, पार्कों इत्यादि अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं के विकास के लिए 14 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न भागों में 25 सड़क-किनारे की सुविधाओं में से 17 को विकसित किया जा चुका है, और शेष का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री ने शुरू की निःशुल्क इंसुलिन योजना

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर के साथ होटल हॉली-डे-होम में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 18 वर्ष आयु से कम के मधुमेह रोगियों के लिए निःशुल्क इंसुलिन योजना 'इलैक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य कार्ड योजना' सहित छः नई स्वास्थ्य योजनाओं की शुरूआत की। हिमाचल प्रदेश योजना की शुरूआत करने वाला

दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र का पहला राज्य बन गया है।

उन्होंने हि.प्र. सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण योजना, स्वास्थ्य बुलेटिन विवरणिका, हेमोफिलिक रोगियों के निःशुल्क उपचार के लिए योजना के शुभारंभ सहित 'मिजल्स रूबेला' अभियान की भी शुरूआत की। स्वास्थ्य कार्ड 'हेल्थ कार्ड एचपी' नामक गुग्गल ऐप से डाउनलोड किए जा सकते हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला के विशेष वार्ड खण्ड की ऑनलाइन आधारशिला भी रखी। आईजीएमसी में अब 32 विशेष वार्ड होंगे।

इस अवसर पर जनसमूह को सम्बोधित करते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि 'मेरा हमेशा ही यह मत रहा है कि स्वास्थ्य अधोसंरचना, शिक्षा, सड़क इत्यादि के विस्तार की बात हो अथवा अन्य विकास योजनाओं का निर्माण हो, जो भी कार्य किया जाए वह गुणात्मक व समयबद्ध होना चाहिए तथा प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए'।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश भर में स्कूलों, कॉलेजों व कार्यालय भवनों का सुनियोजित ढंग से निर्माण सुनिश्चित बनाया है जिनमें वृद्धाश्रम व अनाथाश्रम भी शामिल हैं। उन्होंने गुणात्मक कार्य के निष्पादन के लिए राज्य की सरकारी निर्माण एजेंसियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो कुछ भी विकास कार्य कर रही है, वे सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक को दृढ़ इच्छाशक्ति से कार्य करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने 18 वर्ष की आयु से कम के मधुमेह रोगियों के लिए निःशुल्क इंसुलिन की योजना के निर्माण में किए गए अनुसंधान व कड़ी मेहनत के लिए डॉ.जे.के. मोक्टा को सम्मानित भी किया।

स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि आज आरम्भ की जाने वाली योजनाओं से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश दक्षिण-पूर्व एशिया में इलैक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य कार्ड आरम्भ करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना में किसी भी योजना के अन्तर्गत न आने वाले लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गैर-संक्रमित बीमारियों के रोगियों के लिए स्क्रीनिंग योजना भी आरम्भ की गई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों को प्राथमिकता के आधार पर गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं तथा राज्य सरकार का लक्ष्य ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करना है ।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मधुमेह रोगियों के लिए डायलिसिस की सुविधा आरम्भ में चार जिलों के क्षेत्रीय अस्पतालों में आरम्भ की गई थी जिसे चरणबद्ध ढंग से प्रदेश के सभी क्षेत्रीय अस्पतालों भी में आरम्भ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को विभिन्न प्रकार की 300 जीवन रक्षक दवाईयां सभी सामुदायिक, प्राथमिक तथा उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध करवाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य 28/1000 प्रति वर्ष की मौजूदा नवजात शिशु मृत्य दर को कम कर 25/1000 प्रति वर्ष तक लाना है। उन्होंने मंत्रिमण्डल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग में पैरा-मैडिकल स्टॉफ के 2000 पद स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य प्रबोध सक्सेना ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में विशेष रूचि दिखाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व में किमोथेरेपी के लिए पीजीआई जाने वाले रोगियों को यह सुविधा अब आईजीएमसी में भी उपलब्ध है, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए निशुल्क है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट में की गई घोषणा को पूरा करने के लिए 18 वर्ष की आयु से कम के मधुमेह टाईप-1 रोगियों को निशुल्क इंसुलिन तथा 'हिमोफिलिक' रोगियों के लिए निःशुल्क उपचार सुविधा आरम्भ की गई। उन्होंने कहा कि सघन देखभाल कार्डियोथोरैसिक सर्जरी, जैनिटो युरिनरी सेवाएं, न्यूरो सर्जरी, रेडिएशन आन्कोलॉजी के लिए दी जाने वाली राशि को 30 हजार रूपये से बढ़ाकर 1.75 लाख रूपये तथा कैंसर रोगियों के लिए यह राशि बढ़ाकर 2.25 लाख रूपये की गई है, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कहीं अधिक है। हिमाचल प्रदेश ऐसी सुविधाएं देने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अन्य योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी ।

कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर विपक्ष का सामना करें :मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह हर हाल में समर्पित व पार्टी के निष्ठावान रहे और आया राम-गया राम की तरह व्यवहार न करें। पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को अनुशासित व समर्पित रहना चाहिए और चुनावों के दौरान विपक्षी दलों के झूठे बहकावे में न आकर उन्हें पार्टी के साथ निष्ठा से खड़े होना चाहिए।

कुठलैहड़ के लोगों को उसी उम्मीदवार को समर्थन देना चाहिए, जिसे पार्टी टिकट देगी और कांग्रेस को एकजुट होकर पार्टी के प्रति निष्ठावान होना चाहिए।

यह बात मुख्मयंत्री वीरभद्र सिंह ने ऊना जिले के कुठलैहड़ विधानसभा के समूर-कलां में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए दी।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने कुठलैहड़ से अपने दम पर चुनाव नहीं जीता है, बल्कि उनकी जीत कांग्रेस पार्टी में एकजुटता की कमी के कारण हुई। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस हाईकमान का विशेषाधिकार है कि वह किसे टिकट देती है और हम सभी को उनके निर्णय का सम्मान करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यद्यपि विधानसभा क्षेत्र से टिकट के अनेक दावेदार है, परन्तु जिसे भी टिकट दिया जाता है सभी कांग्रेसजनों का कर्तव्य बन जाता है कि वह कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाएं। उन्होंने कांग्रेस के लोगों का आहवान किया कि वह कुठलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार को विजयी बनाकर एक उदाहरण प्रस्तुत करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में भाजपा विधायकों के प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है, जबकि भाजपा सरकार जब भी सत्ता में आती है वह केवल अपने विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों पर ही ध्यान देती है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र में नहीं, अपितु तानाशाही में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा क्षेत्रवाद, चरित्रहनन एवं झूठे प्रचार में विश्वास रखती है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि जब भी चुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी, लोगों को उन्हें अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिए, न कि प्रतिस्पर्धा के लिए खड़े होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें एकजुटी होकर कांग्रेस के प्रत्याशियों को विजय दिलानी होगी।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने परिवहन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री जी.एस. बाली व उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ हरोली विधानसभा क्षेत्र के दुलैहड़ में 1.63 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बस स्टैंड़ का लोकार्पण किया और 3.23 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, दुलैहड़ के नए खण्ड का शिलान्यास किया। उन्होंने पाबूवाल में 2.66 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, पालकवाह में 69.20 लाख रुपये की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ चिकित्सक आवास, हरोली में 7.60 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मिनी सचिवालय भवन और खण्ड में 96 लाख रुपये की लागत से निर्मित फुटबाल स्टेडियम का लोकार्पण भी किया।

इसके उपरान्त, मुख्यमंत्री ने 54.33 लाख रुपये की लागत से निर्मित राजकीय उच्च पाठशाला, परोईयांकलां के अतिरिक्त भवन व रायपुर में 86.76 लाख रुपये की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व चिकित्सक आवास का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत धनेट, प्लाटा और दिहार के लिए 6.63 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली ऊठाउ पेयजल योजना का शिलान्यास किया। इस योजना से 32 गांव की लगभग 7000 जनसंख्या लाभान्वित होगी। उन्होंने 4.45 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली ओलिंडा-बोहरू सड़क का भूमि पूजन किया। इस सड़क से 6 गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। सभी विकासात्मक उद्घाटनों सहित हरोली और कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्रों में कुल 29.50 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का लोकर्पण किया गया।

मुख्यमंत्री ने सोलन में किए लगभग 41 करोड़ की परियोजनाओं के लोकार्पण

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सोलन के अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान लोगों को लगभग 41 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं समर्पित की, जिनमें 25.24 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बहुमंजिला मिनी सचिवालय भवन का लोकार्पण भी शामिल है। इस भवन की आधारशिला वीरभद्र सिंह ने 23 फरवरी, 2014 को रखी थी।

मुख्यमंत्री ने 69.10 लाख रुपये की निर्मित पशु पॉली-क्लीनक के लोकार्पण के अलावा 2.80 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पशुपालन विभाग के नाईट्रोजन गैस प्लांट का भी लोकार्पण किया, जिसमें उपकरणों का व्यय भी शामिल है।

मुख्यमंत्री ने 3.70 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पंचायती राज विभाग के प्रशिक्षण केन्द्र तथा 1.52 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित जिला न्यायवादी भवन का भी लोकार्पण किया।

बार एसोसियेशन के सदस्यों से परिचर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने सदस्यों की मांग पर उपायुक्त सोलन से न्यायालय परिसर से सटी जमीन का अधिग्रहण करने तथा इस सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि जिला बार एसोसियेशन के अतिरिक्त खण्ड के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सके।

मुख्यमंत्री ने सोलन में 37 बीघा भूमि पर बनने वाले अत्याधुनिक फल एवं सब्जी मण्डी के नए परिसर की आधारशिला रखी। क्षेत्र के किसानों तथा फल उत्पादकों को सुविधा उपलब्ध करवाने तथा नित्य प्रति के बाजार भाव जानने के लिए इस मण्डी को राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ ऑनलाइन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने 1.57 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राजकीय डिग्री महाविद्यालय सोलन के वाणिज्य खण्ड के अतिरिक्त भवन की भी आधारशिला रखी।

उन्होंने 76.33 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाली पंचायती राज विभाग की पार्किंग, 3.20 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले सैनिक विश्राम गृह तथा 'विकास में जन सहयोग' के अन्तर्गत 1.15 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि से निर्मित होने वाले डॉ. वाई.एस. परमार कला एवं संस्कृति (सिरमौर) सामुदायिक भवन की भी आधारशिलाएं रखी।

नहीं किए समन्वयकों के कोई भी पद विज्ञापित ग्रामीण विकास विभाग

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि विभाग को ग्राम पंचायत, खण्ड, जिला तथा राज्य समन्वयकों की भर्ती के सम्बन्ध में बड़े पैमाने पर दूरभाष पर कॉलज आ रही है तथा पूछताछ की जा रही है।

प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि विभाग ने उक्त पदों की भर्ती के लिए न ही किसी प्रकार की स्वीकृति दी है, और न ही इन पदों को लेकर कोई विज्ञापन दिया गया है। हालांकि, शिमला के शनान स्थित ग्रामीण विकास एकीकृत संस्थान नामक एक निजी संस्था ने इन पदों को विज्ञापित किया है। यह संस्था ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की शाखा नहीं है और न ही सरकार से इसका कोई संबंध है। इसलिए, जो आवेदक इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं अथवा कर चुके हैं, वे इस संबंध में किसी भी परिणाम के लिए निजी तौर पर उत्तरदायी हैं।

जितना एक मूर्ख व्यक्ति किसी बुद्धिमानी भरे उत्तर से नहीं सीख सकता, उससे अधिक एक बुद्धिमान एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न से सीख सकता है..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

भ्रष्टाचार पर चिन्ता नही कारवाई चाहिये

बढ़ते अनियन्त्रित उपभोक्तावाद और गिरते नैकित मूल्यों का परिणा है कि भ्रष्टाचार समाज में बिमारी की तरह फैल रहा है। इसके खिलाफ लोगों को सामूहिक रूप से लड़ना होगा चाहे भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों न हो। भ्रष्टाचार से निपटना सरकार की प्राथकिता होनी चाहिये। सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस सकुरियन जोसफ और जस्टिस आर भानुमति की पीठ ने नोएडा प्लाट आंवटन मामले में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव को दोषी करार देते हुए अपने फैसले में यह सब कहा है। सर्वोच्च न्यायालय की यह चिन्ता एक गंभीर चेतावनी है और इस पर तुरन्त प्रभाव से कारवाई किये जाने की आवश्यकता है। लेकिन यह सब होगा कैसे और कौन करेगा। क्योंकि कोई भी भ्रष्टाचारी स्वयं आकर को तो बताता नही है। कि उसने यह भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार को चिहिन्त करके उसे प्रमाणित करने की जिम्मेदारी जांच ऐजैन्सीयों की है और फिर उसे सजा देना न्यायालय का काम है। लेकिन आज आम आदमी का विश्वास इन दोनों पर से उठता जा रहा है। केन्द्र से लेकर राज्यों तक जांच ऐजैन्सीयों पर सत्तारूढ़ सरकार के दवाब में काम करने का आरोप हर बार लगता रहा है। आज सीबीआई जैसी देश की सबसे बड़ी ऐजैन्सी के पूर्व प्रमुख के खिलाफ गठित की गयी एसआईटी इसी आरोप का प्रमाण है। विजय माल्या का देश से बाहर चला जाना भी इसी का प्रमाण है यही नही वीरभद्र सिंह के मामलें में सहअभियुक्त आनन्द चौहान का बिना किसी फैसले के एक साल से भी अधिक समय से न्यायिक हिरासत में होना और मुख्य आरोपी का बाहर होना जांच ऐजैन्सी और न्यायिक व्यवस्था दोनों पर एक साथ जो सवाल खड़े करता है उसको सामने रखते हुए आम आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का साहस कहां से जुटा पायेगा।

अभी पिछले दिनों अरूणाचल के पूर्व मुख्यमन्त्री काली खो पूल का आत्म हत्या से पिछले दिन लिखा गया चालीस पन्नों का हस्ताक्षिरित पत्र जब सामने आया तो उससे राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री और सर्वोच्च न्यायालय पर अति गंभीर आरोप सामने आयें है इस पत्र से पूरी व्यवस्था कठघरे में खड़ी हो जाती है। इस पत्र पर कोई जांच न करवाया और वहां के राज्यपाल तक को हटा दिया जाना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ किये जाने वाले सारे दावों की हवा निकाल देता है। काली खो पुल के पत्र के बाद जस्टिस सी एस कर्णनन के आरोपों से फिर पूरा देश दहला जाता है। न्यायधीशों पर कर्णनन ने गंभीर आरोप लगाये है लेकिन इन आरोपों पर कोई जांच नही होती है। जस्टिस कर्णनन को तो अवमानना का दोषी पाकर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन उसके जेल जाने के वाबजूद वह आरोप तो अपनी जगह खड़े ही है। इन आरोपों की जांच करवा कर यदि कर्णनन को झूठे आरोप लगाने की सजा दी जाती तो जनता के विश्वास को एक आधार मिलता लेकिन इन दोनों मामलों पर सरकार से लेकर शीर्ष अदालत का खामोश रहना गोस्वामी तुलसी दास जी की रामायण की इसी उक्ति को प्रमाणित करता है कि '' समर्थक को नही दोष गुसाइं' और सर्वोच्च न्यायालय की चिन्ता केवल 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' से अधिक नही जाती है।

इस परिदृश्य में आम आदमी अन्त में यही मानने को विवश हो जाता है कि पैसे के सामने कानून और न्याय दोनों बहुत छोटे पड़ जाते है क्योंकि श्रेष्टता का एक ही मानदण्ड रह गया है और वह है पैसा। अनियन्त्रित उपभोक्तावाद का आधार केवल पैसा हैऔर इसे पाने के लिये समाज का हर वर्ग अपने सार्मथ्य और सुविधा के अनुसार किसी भी सीमा तक जाने के लिये तैयार बैठा है। क्योंकि आज बाजार में इतना कुछ उपलब्ध है। जिसके उपभोग की ईच्छा होना स्वभाविक हो गया है और जब यह जायज साधनों से संभव नही हो पाता है तब इसे पाने के लिये व्यक्ति भ्रष्टता का सहारा ले लेता है। भ्रष्टाचार और अपराध इसी बढ़ती उपभोक्ता संस्कृति के परिणाम हैं। इसे रोकने के लिये शीर्ष अदालतों और सरकारों को प्रमाणित कदम उठाने होंगे जो आज दुर्भाग्य से कहीं नजर नही आ रहे है। लेकिन यह तय है कि यदि समय रहते इस दिशा में गंभीर कदम न उठाये गये तो देश में अराजकता फैलते कोई देर नही लगेगी। क्योंकि आज अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं जो हर वर्ग की एक समान आवश्यकताएं है वह अधिकांश पहुंच से बाहर होती जा रही है। फिर सरकार ने आर्थिक स्थिति सुधारने के नाम पर विमुद्रीकरण और एक देश एक कर जैसे जो कदम उठाये है उससे दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दामों में कोई कमी नही आयी है अब रसोई गैस पर सब्सिडी खत्म करने के प्रस्तावित फैसले से मंहगाई और बढ़ेगी यह तय है । इन सारे फैसलों का अन्तिम परिणाम कवेल भ्रष्टाचार होगा। क्योंकि जब सक्ष्म साधनो का अभाव होता है तो उपभोग्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का सबसे आसान तरीका केवल भ्रष्ट होना ही शेष रह जाता है ऐसे में आम आदमी की आज की बुनियादी आवश्यकताओं शिक्षा,स्वास्थ्य और आवास की सुनिश्चितता के लिये इन क्षेत्रों में बढ़ते निजिकरण पर नीतिगत स्तर पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है इसी के साथ व्यवस्था पर आम आदमी के विश्वास को बनाये रखने के व्यवहारिक उपाय अपनाने होंगे क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में आम आदमी का विश्वास आहत होता जा रहा है जो कालान्तर में घातक सिद्ध होगा।

जैविक खेती का सरताज हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में कृषि गतिविधियों में विविधता लाने के लिए 321 करोड़ रुपये की एक महत्वकांक्षी परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत कृषकों को नकदी फसलें उगाने तथा जैविक खेती को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रदेश के कम से कम पांच जिलों में चल रही इस परियोजना के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और बड़ी संख्या में कृषक जैविक खेती अपनाने के लिए आगे आए हैं, जिसके परिणामस्वरूप बे–मौसमी सब्जियां उगाने में अग्रणी यह प्रदेश अब जैविक खेती अपनाने में भी सरताज बन गया है।

प्रदेश में अब तक लगभग 40 हजार कृषकों को पंजीकृत करके लगभग 22 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के तहत लाया जा चुका है। इस वर्ष 2 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को इस खेती के अंतर्गत लाने तथा 200 जैव–गांव विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों को पुरस्कार प्रदान करने की भी घोषणा की है, जिसमें सर्वोत्तम जैविक कृषक को 3 लाख रुपये का प्रथम, 2 लाख रुपये का द्वितीय पुरस्कार तथा एक लाख रुपये का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

यह योजना प्रदेश के कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर तथा मण्डी में, जापान इंटरनेशनल को–आप्रेशन एजेंसी (जायका) के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में अब तक 212 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं तथा इस वर्ष 80 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना की गतिविधियों का संचालन कृषि विकास सोसायटी द्वारा किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई सुविधाएं विकसित करना, कृषकों को जैविक खेती अपनाने तथा नकदी फसलें उगाने के प्रति प्रेरित करना है।

कृषि विभाग तथा कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप आज प्रदेश में कृषि करने के तौर–तरीकों में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर में अलग से जैविक खेती विभाग स्थापित किया गया है, ताकि इस अभियान को गति व दिशा प्रदान की जा सके। उल्लेखनीय है कि शिमला, सोलन तथा सिरमौर जिलों के कृषक पहले ही जैविक खेती में पंजीकृत कृषक बनने के लिए पहल कर चुके हैं तथा इन जिलों में जैविक खेती लोकप्रिय हो चुकी है। कृषक सब्जियां उगाने में विशेष रूचि दिखा रहे हैं।

गौरतलब है कि प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम रसायनों का प्रयोग होने के कारण यहां जैविक खेती करने की अपार संभावनाएं हैं। एक कृषि सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल में कीटनाशक रसायनों की खपत मात्र 158 ग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि देश में औसतन खपत 381 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। पंजाब की खपत 1,164 ग्राम प्रति हेक्टटेयर है, और यह स्वास्थ्य की दृष्टि से चिंता की भी बात है।

जैविक खेती को बढ़ावा देने में 'वर्मीकल्चर' की अह्म भूमिका होती है, यही कारण है कि प्रदेश सरकार केंचुआ खाद तैयार करने को विशेष प्रोत्साहन दे रही है। कृषकों को वर्मीकम्पोस्ट इकाइयां स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत उपदान उपलब्ध करवा रही है तथा अब तक राज्य में ऐसी 1.50 लाख इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं। इस वर्ष 20 हजार अतिरिद्र वर्मीकम्पोस्ट इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि कृषकों को पर्याप्त मात्रा में यह सुविधा उपलब्ध हो सके।

प्रदेश में वर्मीकम्पोस्ट की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं तथा इस कार्य को व्यावसायिक रूप देने के लिए वर्मीकम्पोस्ट की व्यावसायिक उत्पादन इकाइयां भी स्थापित की गई हैं, जबकि जैव–उर्वरक (बायोफर्टिलाइजर) के उत्पादन के पांच यूनिट लगाए गए हैं, ताकि कृषकों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में बायोफर्टिलाइजर उपलब्ध हो सकें।

इसके अलावा, प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य अनेक योजनाएं चलाई जा रही है तथा आधुनिक उपकरण व वैज्ञानिक खेती व अच्छी किस्म के बीजों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके कारण प्रदेश के कृषकों की आर्थिकी में आशातीत बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि, प्रदेश की 80 प्रतिशत खेती वर्षा पर निर्भर है, फिर भी प्रदेश में रिकार्ड उत्पादन हाने के कारण हिमाचल को खाद्यान्न उत्पादन में सराहनीय बढ़ौतरी के लिए लगातार वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 में कृषि कर्मण्य पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है।

सेलुलर जेल बलिदान का मूर्त रूप

'एस. बालाकृष्णन

ओ, मेरी प्रिय मातृभूमि, तुम क्यों आंसू बहा रही हो?
विदेशियों के शासन का अंत अब होने को है!
वे अपना सामान बांध रहे हैं!
राष्ट्रीय कलंक और दुर्भाग्य के दिन
अब लदने ही वाले हैं!
आजादी की बयार अब बहने को है,
आजादी के लिए तड़ प रहे हैं बूढ़े और जवान!
जब भारत गुलामी की बेडियां तोड़ेगा,
'हरि' भी अपनी आजादी की खुशियां मनायेगा!''

यह 'हरि' कौन हैं, जो अपनी आजादी की खुशियां मनाने को आतुर है? श्री बाबू राम हरि पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियां के रहने वाले थे और 'स्वराज्य' के संपादक थे। उन्हें अपने तीन संपादकीयों को ब्रिटिश हुक्मरानों द्वारा 'राजद्रोह' करार दिये जाने के कारण अंडमान की सेलुलर जेल में 21 वर्ष की कैद हुई थी।

इस तरह भारत की आजादी का ख्वाब संजोने वाले लोगों को ब्रिटिश हुक्मरानों द्वारा ऐसे ही बेरहमी से कुचला गया था। भयानक सेलुलर जेल, बलिदान की ऐसी ही एक वेदी थी। कालकोठरी की सजा के लिए इस विशेष तरह की कोठरियों के इंतजाम वाली (इसलिए इसे सेलुलर जेल का नाम दिया गया) इस जेल का नाम भारत की आजादी के संघर्ष के साथ अमिट रूप से जुड़ा हुआ है।

भारतीय बेस्टिल

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने उचित रूप से ही इस जेल को 'भारतीय बेस्टिल' कहकर पुकारा था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, अंडमान पर जापानियों द्वारा जीत हासिल किए जाने के बाद 8 नवंबर, 1943 को जारी वक्तव्य में नेताजी ने कहा था, ''जिस तरह फ्रांस की क्रांति के दौरान सबसे पहले पेरिस के बेस्टिल के किले को मुक्त कराकर वहां बंद राजनीतिक कैदियों की रिहाई कराई गई थी, उसी तरह भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान अंडमान को भी, जहां भारतीय कैदी यातनाएं भोग रहे हैं, सबसे पहले मुक्त कराया जाना चाहिए।'' (हालांकि बाद में सहयोगी देशों ने इस द्वीप पर दोबारा कब्जा जमा लिया था।)

कैदियों की बस्तियां

ब्रिटिश उपनिवेश भारत और बर्मा में संगीन अपराधों के लिए दोषी ठहराये गये कैदियों के लिए बैंकोलिन (सर्वप्रथम 1787 में), मल्लका, सिंगापुर, अराकान और तेनास्सेरिम में कैदियों की बस्तियां स्थापित की गई। अंडमान की जेल इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी और भारतीय सरजमीं पर स्थापित होने वाली अपने किस्म की पहली जेल थी। हालांकि, इससे काफी पहले 1789 में ही पोर्ट कार्नवालिस, उत्तरी अंडमान में कैदियों की बस्ती स्थापित की गई थी, लेकिन सात साल बाद उसे खाली कर दिया गया था।

ब्रिटिश हुक्मरानों ने आजादी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम (1857), को 'सिपाहियों की बगावत' का नाम दिया था और इसी के मद्देनजर कैदियों की बस्ती का विचार पुन: जीवित हो उठा। तथाकथित बागियों, भगोड़ों और विद्रोहियों को निर्वासित और कैद करने के लिए दूर-दराज के इलाके -अंडमान का चयन किया गया। 10 मार्च, 1858 को 200 'गंभीर राजनीतिक अपराधियों' के पहले जत्थे ने दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के अंतर्गत चाथलाम द्वीप के छोर पर कदम रखा। 216 कैदियों का दूसरा जत्था पंजाब सूबे से आया। 16 जून, 1858 तक यहां पहुंचने वाले कैदियों की कुल तादाद 773 हो गई, 64 कैदियों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था, फरार होने और दोबारा हाथ न आने वाले कैदियों की संख्या 140 थी, एक कैदी ने आत्महत्या की थी, फरार होने के बाद दोबारा पकड़े जाने पर फांसी पर लटकाये गये कैदियों की संख्या 87 थी, यह जगह छोड़ने वाले कैदियों की संख्या 481 थी। 28 सिम्तबर, 1858 तक यहां करीब 1330 कैदी पहुंच चुके थे। 1858 और 1860 के बीच देश के कोने-कोने से लगभग 2,000-4,000 स्वाधीनता सेनानियों को अंडमान भेजा जा चुका था। दुखद बात यह है कि उनमें से अधिकांश ने जीने की और कार्य करने की बेहद पीड़ा दायक परिस्थितियों के कारण दम तोड़ दिया। फरार होकर जंगल की ओर भागने वालों में से कोई भी जीवित न बच सका। बाद में आपराधिक मामलों में दोषी ठहराये गए लोगों को भी कड़ी सजा के लिए यहीं भेजा जाने लगा। एक सदी के बाद, 15 अगस्त, 1957 को पोर्ट ब्लेयर में 'शहीद स्तम्भ' प्राण न्यौछावर करने वाले अचर्चित और गुमनाम शहीदों को समर्पित किया गया।

सेलुलर जेल

ब्रिटिश हुक्मरानों को डर था कि राजनीतिक कैदी दूसरे कैदियों के बीच अपने क्रांतिकारी विचारों को फैलाने लगेंगे और उनके समूह के साथ घुलने-मिलने लगेंगे। लिहाजा, उन्होंने एक दूर-दराज के इलाके में कालकोठरियां बनाने का फैसला किया। इस प्रकार 1906 में कुख्यात सेलुलर जेल पूर्ण हो गई, जिसकी कालकोठरियों की संख्या बढ़कर 693 हो गई! जैसे-जैसे स्वाधीनता संग्राम जोर पकड़ने लगा, 1889 में पूना से 80 क्रांतिकारियों को निर्वासित कर यहां भेजा गया। जैसे-जैसे स्वाधीनता संग्राम में उफान आया, 132 लोगों (1909- 1921), उसके बाद (1932-38) में 379 लोगों को यहां भेजा गया। विभिन्न तरह के षडयंत्र के मामलों में शामिल राजनीतिक कैदियों को सेलुलर जेल भेजा गया। इनमें से कुछ मामलों में अलीपुर बम मामला (माणिकटोला षडयंत्र मामले के नाम से भी चर्चित),नासिक षडयंत्र मामला,लाहौर षडयंत्र मामला (गदर पार्टी के क्रांतिकारी),बनारस षडयंत्र मामला, चटगांव शस्त्रशाला मामला, डेका षडयंत्र मामला,अंतर-प्रांतीय षडयंत्र मामला, गया षडयंत्र मामला और बर्मा षडयंत्र मामला आदि शामिल हैं। इनके अलावा, वहाबी विद्रोहियों,मालाबार तट के मोपला प्रदर्शनकारियों,आंध्र के रम्पा क्रांतिकारियों, मणिपुर स्वाधीनता सेनानियों, बर्मा के थावरडी किसानों को भी अंडमान भेजा गया।

जेल में जीवन

सेलुलर जेल में जीवन विशेषकर शुरुआती कैदियों के लिए बेहद अमानवीय और बर्बर था। राजनीतिक कैदियों को बहुत कम भोजन और कपड़े दिये जाते थे और उनसे कड़ी मशक्कत कराई जाती थी। ऐसी कठोर मेहनत की आदत न होने के कारण वे अपना रोज के काम का कोटा पूरा नहीं कर पाते थे, जिसके कारण उन्हें

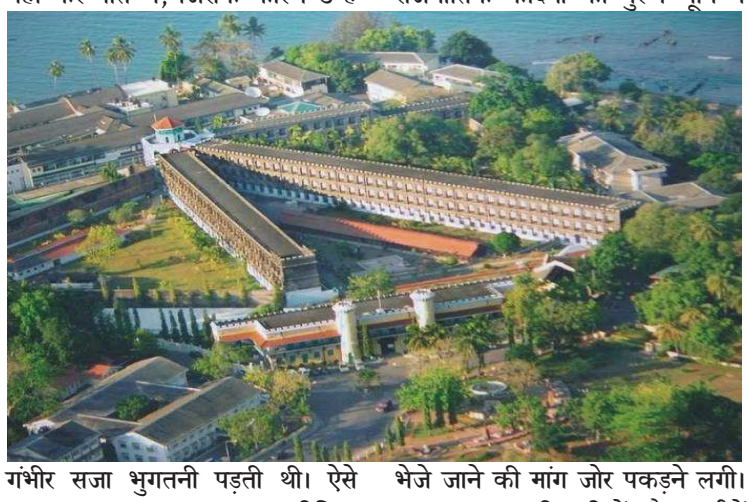

गंभीर सजा भुगतनी पड़ती थी। ऐसे व्यवहार का मकसद उन राजनीतिक कैदियों को अपमानित करना और उनकी इच्छा शक्ति को तार-तार करना था। उन्हें कोल्हू पर जोता जाता था, उनसे नारियल छिलवाये जाते थे, नारियल के रेशों की पिसाई कराई थी, रस्सी बनवाई जाती थी, पहाड़ तोड़ने के लिए भेजा जाता था, दलदली जमीन की भरत कराई जाती थी, जंगल साफ कराये जाते थे, सड़कें बिछवाई जाती थी आदि। सबसे भयानक काम 'मोटे सान की कटाई' बहुत अधिक अम्लता वाली रामबन घास, 'रस्सी बनाने की कला' थी, जिसके बाद लगातार खुजली, खरोंचना और रक्तस्राव जैसे तकलीफें होती थीं!

भूख हड़ताल

जुलाई 1937 में जब भारत के सात सूबों में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ, तो सेलुलर जेल के राजनीतिक कैदियों को मुख्य भूमि में भेजे जाने की मांग जोर पकड़ने लगी। जब बार-बार की अपीलों और प्रदर्शनों का कोई नतीजा न निकला तो उनमें से 183 लोग 24 जुलाई, 1937 से, 37 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गये। इससे उनके समर्थन की लहर उठी और मुख्य जेलों में बंद उनके साथियों ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी। देश भर में विराध प्रदर्शन हुए। आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा और 22 सितंबर 1937 को स्वाधीनता सेनानियों का पहला जत्था अंडमान से रवाना हुआ। आखिरी जत्था भी 18 जनवरी, 1938 तक अंडमान से रवाना हो गया। आपराधिक मामलों के दोषियों की वहां से रवानगी 1946 तक जारी रही, जब कैदियों की इस बस्ती को बंद कर दिया गया।

राष्ट्रीय स्मारक

इस जेल में अनेक करिश्माई हस्तियों को बंदी बनाकर रखा गया। उनमें अन्य लोगों के अलावा सावरकर बंधु,मोतीलाल वर्मा, बाबू राम हरि,पंडित परमानंद,लद्दा राम, उलास्कर दत्त, बरिन कुमार घोष, भाई परमानंद, इंदु भूषण र य,पृथ्वी सिंह आजाद, पुलिन दास, त्रैलोकीनाथ चक्रवर्ती, गुरुमुख सिंह शामिल हैं। यह फेहरिस्त लंबी और विशिष्ट है। सेलुलर जेल में बंद रहे हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के अमूल्य बलिदान की याद और सम्मान में 11 फरवरी, 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया गया। वहां का संग्रहालय और साउंड एंड लाइट शो जेल के कठिन जीवन की झलक प्रस्तुत करते हैं,जहां उन लोगों ने सिर्फ इसलिए कुर्बानियां दी, ताकि हम आजादी और शांति के साथ जी सकें। सेलुलर जेल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उसकी तुलना में कोई और स्थान नहीं है।

किसी जमाने में भयावह स्थान रही यह सेलुलर जेल, अब एक राष्ट्रीय स्मारक बन चुकी है, जो बलिदान का मूर्त रूप है, एक ऐसा स्थान है, जो हमें याद दिलाता है कि हमें आजादी बड़ी मुश्किलों से मिली है।

योग:एक क्रांति का सूत्रपात

डॉ. एच आर नागेन्द्र

योग ने यूं तो हमेशा से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है, पर पिछले तीन वर्षो के दौरान योग को लेकर आम लोगों की जागरूकता में आमूल चूल बदलाव देखने में आया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के जवाब में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की तत्काल 187 देशों सराहना की गई एवं इसे प्रायोजित किया गया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ने योग को दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए जीवन की एक शैली के रूप में बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही, भारत ने एक प्राचीन अभ्यास को साझा किया है जिसे अब सांस्कृतिक, धार्मिक, राष्ट्रीय एवं भाषाई बाधाओं के भेदभाव से अलग दुनिया के लगभग सभी देशों ने अपना लिया है और इस प्रकार उन्होंने भारत के मूलभूत संदेश 'विविधाता में एकता'को मजबूती प्रदान की है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) एक असाधारण पैमाने पर दुनिया भर के करोड़ो लोगों को एक साथ लाने में सफल हुआ है और इसने पूरे विश्व में प्रेम, शांति और सद्भाव का संदेश फैलाया है।

पश्चिम देशों में, योग को मूलभूत रूप से शारीरिक शक्ति और लचीलेपन को बेहतर बनाने के लिए एक शारीरिक क्रिया या व्यायाम माना जाता है। लेकिन, 'योग' का अर्थ ही होता है 'जोड़' अर्थात चेतना की उच्चतर अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए दिमाग, शरीर और आत्मा का संयोजन।

तथाकथित 'गॉड पार्टिकल' की खोज सहित प्रमात्रा भौतिक विज्ञान में हाल की प्रगति के साथ विज्ञान ने अपनी सीमाओं को महसूस करना और पारंपरिक न्यूनीकरण ढांचे से आगे देखना आरंभ कर दिया है। ज्ञान योग विज्ञान को भौतिक संरचना से आगे निकलने का निर्देश देता है जिससे कि मानवीय आयामों के पांच स्तरों की पहचान की जा सके।

भारत में वेदों के रूप में वैज्ञानिक चिंतन की एक लंबी परंपरा रही है जिसे सभी ज्ञान आधार के आरंभिक स्रोत के रूप में जाना जाता हैऔर इसी वजह से योग के उदभव का वेदों में होना कोई अपवाद की बात नहीं है। योग की चार धाराएं-ज्ञान, भक्ति, राज और कर्म योग बौद्धिक, भावनात्मक, इच्छा शक्ति और कर्म स्तरों पर कार्य करती हैं और व्यक्तित्व का समग्र रूप से विकास करती हैं। इसमें सभी लोगों के लिए एक संदेश है जैसाकि स्वामी कुवालयानंद ने दशकों पहले कहा था और बहुत पहले 1940 के दशक में योग में वैज्ञानिक अनुसंधान का अन्वेशण किया था। 1973 में प्रकाशित, योगी सत्यमूर्ति पर किए गए एक अध्ययन में नोट किया गया था कि वह नौ घंटों तक हृदय की विद्युतीय गतिविधि को स्वैच्छिक रूप से रोक पाने एवं उसके बाद स्वाभाविक रूप से उसे पुनरुज्जीवित कर सामान्य स्थिति में ले आने में सक्षम थे। दूसरे अध्ययन में, एक बौद्ध ध्यान तकनीक के मानने वाले (बेन्सन एवं अन्य, 1982) अपने शरीर के तापमान को 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक बढ़ा पाने में सक्षम थे। अनुसंधान में महर्षि महेश योगी के योगदान से दुनिया भर में टीएम (ट्रांसेडेन्टल मेडिटेशन) द्वारा विश्रांति प्रतिक्रिया का आयाम सामने आया। मधुमेह, कैंसर, दिल की बीमारियों आदि जैसी एनसीडी से निपटने के लिए आधुनिक चिकित्सा की एक अतिरिक्त पद्धति के रूप में योग के उपयोग ने आनुवांशिकी, मस्तिष्क के बदलावों, मनोविज्ञान, एवं शरीर क्रिया विज्ञान जैसे माध्यमों की समझ के जरिये इस तंत्र के साथ बेहद आशाजनक परिणाम प्रदर्शित किए हैं। बंगलुरू स्थित एस-वीवाईएएसए योग विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे अनुसंधानों की पहल की जा रही है जोकि वर्तमान में योग अनुसंधान को समर्पित विश्व का एकमात्र पूर्ण विकसित विश्वविद्यालय है।

हमारे प्रधानमंत्री इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि उनके प्रयासों की बदौलत योग अब केवल एक दिन के समारोह तक ही सीमित नहीं रह गया है बल्कि एनसीटीई, एनसीईआरटी द्वारा योग को प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर एक अनिवार्य विषय बनाए जाने के जरिये इसे अब हमारी शिक्षा प्रणाली में शामिल कर लिया गया है। यूजीसी भी पीछे नहीं रहा है और अनुसंधान के बारे में पढ़ाने तथा सभी लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए योग्य व्यक्तियों को तैयार करने के लिए उसने योग को उच्चतर शिक्षा प्रणाली में शामिल कर लिया है। पसूका

500 जल रक्षकों 262 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती को केबिनेट की मंजूरी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश की वीरभद्र सरकार की केबिनेट ने 500 जलरक्षकों व कालेज केडर के 262 सहायक प्रोफेसरों को काट्रेक्ट पर भरने की मंजूरी दी। हालांकि इन पदों को सरकार भर पाएगी इस पर संशय हैं। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चूंकि अक्तूबर में आचार संहिता लग जाएंगी, ऐसे में इन पदों को भरने के लिए समय नहीं बचेगा।

वीरभद्र सिंह केबिनेट ने 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके दृष्टि बाधित व्यक्तियों के पक्ष में सीधी भर्ती कोटा पदों के विरूद्ध सेवाएं तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक तथा अन्य योग्यता में छूट देने का निर्णय लिया है। मंत्रिमण्डल ने दृष्टि बाधितों के लिए कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अन्य योग्यता में अर्थात कम्प्यूटर साईस में डिप्लोमा में भी छूट दी है। चयनित दृष्टिबाधित व्यक्ति नियुक्ति के उपरांत भर्ती नियमों के दृष्टिगत वांछित डिप्लोमा पूरा करने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा तथा सम्बन्धित विभाग द्वारा उन्हें बुनियादी कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में निर्णय लिया गया कि पीजीटी (आईटी) अध्यापक अब निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा मौजूदा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को निरस्त कर भर्ती किए जाएंगे तथा इस सम्बन्ध में एक समिति गठित की जाएगी और मामला लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर कर दिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने 60 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के नागरिकों, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत नामांकित हैं, के उपयोग के लिए अतिरिक्त बीमा कवर के माध्यम से उपचारात्मक वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की आसान पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को भी स्वीकृति प्रदान की। योजना पात्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लाभान्वित परिवार में 30 हजार रुपये प्रति वर्ष प्रति वरिष्ठ नागरिक को अतिरिक्त कवरेज प्रदान करेगी। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी किसी भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सूचिबद्ध अस्पतालों में कैशलैस उपचार प्राप्त रकने के योग्य होगा। वर्तमान में राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत 1,30,587 वरिष्ठ नागरिकों को नामांकित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की आयोजित बैठक में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप भर्ती की उपयुक्त प्रक्रिया अपनाकर अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के माध्यम से रोगी कल्याण समितियों के तहत नियुक्त स्टाफ नर्सो तथा अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को राज्य के अन्य अनुबंध कर्मचारियों की तर्ज पर तीन वर्ष के सेवाकाल के उपरांत नियमितिकरण के लिए संस्तुति की जाएगी।

हिमाचलियों को लाभान्वित करने तथा दूरवर्ती क्षेत्रों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिमाचलियों द्वारा स्थापित 100 किलोवाट तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया कि ऐसी परियोजनाओं से हि.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड सीमित बिजली खरीदेगा। इन परियोजनाओं के लिए रायल्टी की दर प्रथम 12 वर्षो के लिए 2 प्रतिशत, 13 से 30 सालों के लिए 12 प्रतिशत तथा 31 से 40 वर्षो के लिए 18 प्रतिशत होगी।

विद्युत उत्पादकों को एक बड़ी राहत प्रदान करते हुए मंत्रिमण्डल ने उन परियोजना के लिए जिनकी स्थापित क्षमता, क्षमता वृद्धि के उपरांत 5 मेगावाट से अधिक हो, के प्रभार को 20 लाख रुपये प्रति मेगावाट से एक लाख रुपये प्रति मेगावाट तक कम करने अथवा दर्शाया गया उत्तरार्द्ध प्रीमियम जो भी अधिक हो। यह प्रावधान केवल उन

परियोजनाओं के लिए लागू होगा, जहां क्षमता में वृद्धि करने के लिए संशोधित क्षमता अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं किए गए हों तथा उन सभी परियोजनाओं के लिए जिनकी इस प्रावधान की अधिसूचना के उपरांत क्षमता वृद्धि होगी। उपरोक्त प्रावधान उन परियोजनाओं के लिए लागू नहीं होंगे, जहां संशोधित क्षमता समझौतों को पहले ही मंजूरी दे दी गई है और हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

मंत्रिमण्डल ने शिमला में स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की। शिमला स्मार्ट सिटी में शहर सलाहकार फोरम के रूप में एक मजबूत सलाहकार तंत्र होगा, जिसमें योजनाबद्ध और कार्यान्वयन के लिए सभी चरणों में एसपीवी को समर्थन देने के लिए सभी हितधारकों का समावेश होगा।

मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री की घोषणा को पूरा करते हुए भविष्य में विशेष पुलिस अधिकाारियों के मानदेय को 4 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रुपये प्रतिमाह करने को मंजूरी प्रदान की। यह पुलिस अधिकारी राज्य पुलिस और जम्मू व कश्मीर की सीमावर्ती जिलों चम्बा तथा लाहौल-स्पीति की दुर्गम एवं दूरवर्ती क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करते हैं। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त जिलों में 518 विशेष पुलिस अधिकारियों की सेवाओं को मंजूरी दी गई है।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

मंत्रिमण्डल ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार पीटीए के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल करने की अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष अर्थात 16 अगस्त, 2021 करने तथा पीटीए (जीआईए) को आठ दिनों के बजाया 10 दिनों का चिकित्सा अवकाश तथा 10 दिनों का आकस्मिक अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने छूटे हुए 97 पैरा अध्यापकों को सम्बन्धित पदों का नियमित स्केल प्रदान करने को मंजूरी दी।

बैठक में प्राथमिक सहायक अध्यापकों को कलैण्डर वर्ष में 10 दिन का चिकित्सा अवकाश तथा 10 दिन का आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त निजी अनुराध पर खाली पद के विरूद्ध एक मुश्त स्थानान्तरण की नीति बनाने को मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने मिड-डे-मील योजना के तहत तैनात रसोइ एवं सहायकों को 1500 रुपये प्रतिमाह मानदेय प्रदान करने तथा सिलाई अध्यापिकाओं के सहायता अनुदान को बढ़ाकर 6300 रुपये करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने गत माह आयोजित बैठक में मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत सेब का प्रापण मूल्य 6.75 रुपये प्रति किलोग्राम करने का मंजूरी प्रदान की थी और अब किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए इसे बढ़ाकर 7 रुपये प्रति किलोग्राम करने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा के धीरा में एसडीएम कार्यालय तथा मण्डी जिले के नेरचौक में उप कोषागार कार्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज मण्डी तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज चम्बा के लिए आउटसोर्स आधार पर श्रमशक्ति हायर करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, पात्र उम्मीदवारों की उपलब्धता की शर्त पर नीट-यूजी मैरिट आधार पर तिब्बती शरणार्थियों में से मेडिकल कॉलेज नाहन में एक सीट तथा चम्बा मेडिकल कॉलेज में दो सीटें प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के पंजेहड़ा में उप तहसील खोलने, शिमला ग्रामीण के भदबानी तथा शिमला जिले के कोटखाई के महासू व बगाहर, किन्नौर जिला के पंगी तथा कल्पा, मण्डी के परवाड़ा, धरोट (चच्योट) बड़ा गांव (पधर), कारला (नीहरी), सोलन के बड़ोग, घड़सी (उप तहसील कृष्णगढ़) तथा सहरोल (अर्की) में नया पटवार वृत्त खोलने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा करते हुए कांगड़ा जिले के लगदू में उप तहसील खोलने, शिमला जिला के जांगला तथा सरस्वती नगर में उप तहसील खोलने तथा सोलन जिला की उपतहसील रामशहर को तहसील में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने हाल ही में की गई घोषणा के अनुरूप मण्डी जिला के पधर में स्टाफ सहित उप रोजगार कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने निरीक्षणों की और प्रभावी योजना के लिए श्रम एवं रोजगार हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व उद्योग इत्यादि विभागों को सम्मिलित करते हुए व्यापार को सरल करने के लिए हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय निरीक्षण व्यवस्था की स्थापना को मंजूरी प्रदान की।

पंचायतों के अभिवेदन के अनुसार मंत्रिमण्डल ने ग्राम पंचायत खटनौल (शिमला) की परिसीमा का क्षेत्र पुलिस स्टेशन सुन्नी के अन्तर्गत तथा मैहतपुर की ग्राम पंचायत चंगर-हंडोला को पुलिस स्टेशन ऊना तथा ग्राम पंचायत संतोषगढ़ को ऊना सदर पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत स्थानान्तरित करने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के बनलगी (कुठाड़) तथा कांगड़ा जिला के डाडासीबा तथा देहरा में प्रत्येक अग्निशमन चौकी के लिए निर्धारित पद्धति के अनुसार 7-7 तकनीकी पदों के सृजन सहित अग्निशमन चौकियां खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में टेलीमेडिसीन परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप कांगड़ा जिला के राजकीय उच्च पाठशाला (छात्रा) रैहन को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में सिरमौर जिले के मां नगरकोटी मेला नारंग, राम नावमी मेला नैना टिक्कर, गुग्गा नवीं मेला पाबियाना (धवाग) तथा मण्डी जिला के माता गड़ा दुर्गा गुसैन मेले को जिला स्तरीय मेले घोषित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

पद सृजित व भरने

मंत्रिमण्डल ने सरप्लस पूल से परिवर्तित करने सहित विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसरों (कालेज कैडर) के 262 पदों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप अनुबन्ध आधार पर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में ग्राम पंचायतों की प्रत्येक क्रियाशील सिंचाई तथा पेयजल योजनाओं में कम से कम एक स्टाफ कर्मचारी को सुनिश्चित बनाने के लिए 500 जल रक्षक तैनात करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। वह दिन में दो बार जल वितरण तथा भंडारण टैंकों के कलोरिनेशन, सूक्ष्म मुरम्मत करने तथा विभाग को रिसाव की रिपोर्ट करने के अलावा भंडारण टैंकों की सफाई व कीटाणु रहित बनाना सुनिश्चित करेंगे।

मंत्रिमण्डल ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में छूट देते हुए शहरी एवं ग्राम नियोजन विभाग में वरिष्ठ योजना ड्रासमेन श्रेणी-2 के 2 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के नापतोल संगठन में अनुबन्ध आधार पर निरीक्षक विधिक माप-पद्धति के चार पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने नए खोले गए राजकीय जवाहर लाल नेहरू ललित कला महाविद्यालय चौड़ा मैदान शिमला में सरप्लस पूल से सेवादार के तीन पद और चौकीदार के दो पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व विशेष रूप से सक्षम निदेशालय में अनुबन्ध आधार पर आशुलिपिकों के दो पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने महिला एवं बाल विकास विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी प्रोग्रामर के एक पद के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के दो रिक्त पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने के अतिरिक्त दिहाड़ी आधार पर चतुर्थ श्रेणी के तीन पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने डॉ. वाई.एस. परमार उद्यानिकी एवं वाणिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन में अनुबन्ध आधार पर लोक सम्पर्क अधिकारी के एक पद को भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में बागवानी विभाग में प्रयोगशाला सहायक के 10 पदों को भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने ऐसे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में जहां 25 व 25 से अधिक विद्यार्थियों ने संगीत विषय को चुना है, में संगीत प्रवक्ताओं के पदों को सृजित व भरने पर सहमति प्रदान की।

स्वास्थ्य

बैठक में ऊना जिला के स्वास्थ्य उप-केन्द्र चमेरी को एक पद चिकित्सा अधिकारी, एक पद फार्मासिस्ट व एक पद चतुर्थ श्रेणी सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने और स्वास्थ्य उप केन्द्र चमेरी को इसी ग्राम पंचायत के भीतर बदलने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला के ईएसआई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गगरेट को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में पदों के सृजन सहित स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में नागरिक अस्पताल डलहौजी को 18 पदों के सृजन सहित 50 बिस्तरों के अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोपालपुर को 12 पदों के सृजन सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में शिमला जिला जुब्बल के कुठाड़ी में तीन पदों के साथ सृजन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सोलन जिला के चंडी पशु औषधालय को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में देहरा खण्ड के गांव खबली तथा रोहडू तहसील की रतनाड़ी ग्राम पंचायत के जाखड़ गांव में प्रत्येक में चार पदों के साथ आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने आईजीएमसी तथा टांडा मेडिकल कालेज कांगड़ा में संकाय स्टाफ के साथ अस्पताल प्रशासन विभाग सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में कुल्लू जिला के भुंतर के नागरिक अस्पताल तेगुबेहड के लिए पैरा मेडिकल स्टाफ के 19 पद स्वीकृत किए गए।

मंत्रिमण्डल ने केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत 6 पदों को सृजित कर प्रदेश के लिए सचल खाद्य जांच प्रयोगशालाएं उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया।

बैठक में सिरमौर जिला के मिसरवाला में दो पदों को सृजित कर स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अधिनियम/नियम

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों के भर्ती एवं पदोन्नति तथा अन्य सेवाएं की शर्तें) नियम-2-17 को बनाने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। संशोधन के तहत अधिनियम की धारा-12 (6) के तहत कुलपति को तीन वर्षो की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और वह आगामी तीन वर्षो के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए भी योग्य होगा, परन्तु उसकी आयु 70 वर्ष से अधिक न हो।

मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में मध्यम, लधु व सूक्ष्म उद्योगों को फिर से चालू करने के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की। इस सम्बन्ध में एक उप-समिति गठित की जाएगी।

संवदेनशील मुद्दों पर राजनीति न करे विपक्ष:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सोलन में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि विपक्ष निर्दोश लड़की 'गुड़िया' की मौत पर राजनीति कर रहा है और चम्बा जिले के तीसा में अशांति के लिए भी विपक्ष जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जो लोग लूटपाट व अशांति फैलाने तथा सरकारी संपति को नुकसान पहुंचाने में शामिल हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि निजी स्वार्थ के लिये इस प्रकार की घटनाओं को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए और भाजपा नेताओं को गुडिया के प्रति सहानुभूति के बजाए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये मामले को तूल दे रहे हैं।

तीसा में हुई झड़पों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और आज दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों द्वारा शांति मार्च का आयोजन किया गया तथा शांति एवं सौहार्द कायम बनाए रखने की शपथ ली गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने आयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर काफी हो-हल्ला किया और यहां तक कि इसके लिए धन भी एकत्रित किया, लेकिन आज तक मंदिर नहीं बन पाया। उन्होंने सवाल उठाया कि यह महज मतदाताओं को लुभाने के लिए भाजपा का राजनीतिक प्रचार है।

मुख्यमंत्री ने राज्य में गत साढ़े चार वर्षो के दौरान हुए विकास की चर्चा करते हुए कहा कि हिमाचल देश का सर्वाधिक साक्षर राज्य बन कर उभरा है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्धियों द्वारा कांग्रेस पार्टी के किसी भी सदस्य अथवा नेता पर हमले का जबाव देना संगठन का दायित्व है। पार्टी 'ऑल फार वन तथा वन फॉर ऑल' के फार्मूले को अपनाने के बजाय आरोपों पर चुप रहती है। उन्होंने कहा कि राज्य, जिला अथवा खण्ड स्तर पर पार्टी संगठन को भाजपा अथवा अन्य राजीनतिक विरोधियों द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोपों तथा दुष्प्रचार का एकजुट होकर विरोध करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह विपक्ष को जवाब व उत्तर देने के लिए सक्षम है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए राज्य, जिला तथा खण्ड स्तर पर कांग्रेस समितियां का गठन किया गया है। पार्टी कैडर को संयुक्त रूप से विपक्ष के झूठे प्रचार का सामना करने तथा लोगों को विपक्ष की ओच्छी चालों के बारे अवगत करवाने के लिए आगे आना चाहिए।

उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. धनी राम शांडिल द्वारा उठाई गई मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया और कहा कि वह नौणी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा गिरि नदी से नई जलापूर्ति योजना की मांगों का विश्लेषण करेंगे।

मंत्री ने सोलन में 41 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया।

राज्य वन विकास निगम का Eco-Tourism को बढ़ावा देने का निर्णय

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में वनों का क्षेत्र 37,033 किमी है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 66. 52 प्रतिशत हिस्सा है। वानिकी प्रबंधन में हिमाचल प्रदेश सरकार की रणनीति वनो के तर्कसंगत उपयोग के साथ साथ इसके विस्तार व संरक्षण की है।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक के रूप में मान्यता है क्योंकि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग 7. 0 प्रतिशत है व इसे भविष्य के लिए विकास के एक प्रमुख इंजन के रूप में महसूस किया जा रहा है । राज्य पर्यटन गतिविधियों के लिए बुनियादी संसाधनों जैसे भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता, स्वच्छ और शांतिपूर्ण वातावरण, स्वच्छ नदियों, पवित्र तीर्थ स्थानों, ऐतिहासिक स्मारकों और दोस्ताना व मेहमाननवाज लोगों से संपन्न है।

राज्य में पर्यटन के योगदान को बढ़ाने के लिए पारिस्थितिकी के साथ एकीकृत करने के उद्देश्य से, वन विभाग ने हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के माध्यम से पारिस्थितिकी पर्यटन (Eco-Tourism) को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य व्यापक पर्यटन के साथ आने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है और इसके इलावा स्थानीय रूप से उपलब्ध, परंपरागत, पुनर्नवीनीकरण सामग्री और बुनियादी सुविधाओं जो कि पर्यावरण के अनुकूल हों-को बढ़ावा देना है।

पर्यावरण पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिए विभाग द्वारा लगभग 50 साइटें निगम को सौंपी जा रही हैं। पर्यटक को गुणवत्ता सेवा प्रदान करने के लिए, निगम पर्यावरणीय मानदंडों में पर्यटकों को विश्व स्तरीय सेवाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से कार्य करेगा। साइटों का विकास राज्य की मौजूदा पर्यटन स्थलों पर दवाब को कम करने में मदद करेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। साइटों को अगले पर्यटन सत्र से पहले सितंबर और अक्तूबर 2017 में चालू होने की उम्मीद है।

पारिस्थितिकी पर्यटन पर उपरोक्त कार्यो से, निगम पर्यावरण के अनुकूल उपायों के माध्यम से जिम्मेदार पर्यटन के लिए पर्यटन स्थल उपलब्ध करवाएगा जिससे जंगलों के संरक्षण के साथ साथ अर्थव्यव्थ को भी लाभ होगा।

फाइनल में हार के बाद ड्रेसिंग रूम में महिला क्रिकेटरों का था ये हाल

शिमला/शैल। इंग्लैंड में हुए आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में हारने के बाद इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में पांच बजे से शाम आठ बजे तक (इंग्लैड का समय) पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया था। उदासी का आलम ये था कि किसी ने किसी से एक भी शब्द नहीं बोला था। चहुं ओर चुप्पी थी। कोई कुछ नहीं कर रहा था।

ये खुलासा आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम की विकेट कीपर सुषमा वर्मा ने राजधानी शिमला में अभिनंदन समारोह में किया। वो बोली, 'हम ठीक नहीं खेलें। बहुत बुरा लग रहा था कि हम इतना क्लोज मैच हार गए।'

जिला शिमला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस अभिनंदन समारोह में अंतराष्ट्रीय महिला व पुरूष क्रिकेट में प्रदेश की इस पहली खिलाड़ी ने कहा कि 'हम सब बहुत उदास हो गए थे, हमें लगा कि हमने बहुत कुछ खो दिया।' वहां काम करने वाले लोगों ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या कर दिया हैं।'आप लोगों को खुश होना चाहिए।' जब आप अपने देश जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या कर दिया है।

सुषमा ने कहा कि वो बिल्कुल सही थे। जब हम मुबंई पहुंचे तो जिस तरह का स्वागत हुआ वो लाजवाब था व हमें तब लगा कि हमने क्या कर दिया। हालांकि फाइनल में हार का गम वो अपने जहन से अलग नहीं कर पाई। जब ग्रैंड होटल के हॉल में शिमला कि युवा क्रिकेटरों व जिला शिमला क्रिकेट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने खड़े होकर तालियों से उनका अभिनंदन किया तो वो विनम्रता से बोली, 'हम इतना डिजर्व नहीं करते, फिर भी इस अभिनंदन के लिये धन्यवाद।'

17 साल की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में कदम रखने वाली जिला शिमला के सुन्नी के ये महिला क्रिकेटर दुनिया की बेस्ट विकेट कीपरों में शुमार हैं।

वो टीम में विकेटकीपर कैसे बनी, इस बावत भी इस महिला खिलाड़ी ने मासूमियत में दिलचस्प वाक्या सुनाया। वो बोली,'जब वो अकादमी में गई तो उन्हें नहीं मालूम था कि गेंदबाजी पूरी बाजू घुमाकर करनी होती थी। ये उन्हें

वहीं पता चला।'वो सीधे तेजी से गेंद फेंकती थी। लेकिन इस तरह गेंदबाजी तो होती नहीं। तो गेंदबाजी छोड़नी पड़ी। उस समय चौके-छक्के भी ज्यादा नहीं लग रहे थे। तब और क्या बचा था, बस विकेटकीपिंग। तो विकेट कीपर बन गई।'

अपने दादा जो खुद वालीवॉल के अच्छे खिलाड़ी थे, के अलावा एडम गिलक्रिस्ट व सचिन तेंदुलकर को प्रेरणा स्त्रोत मानने वाली शिमला जिला की इस अंतराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर ने कहा कि अब वो विराट कोहली व महेंद्र सिंह धोनी के नक्शेकदम पर हैं।

राजधानी के पोर्टमोर स्कूल में पढ़ी सुषमा ने कहा कि उनके सबसे बड़े रोल मॉडल तो उनके दादा हैं। उन्हीं की प्रेरणा से वो क्रिकेट की दुनियां में हैं। वह बोली, जब न्यूजीलैंड से मैच होते थे वो दादा के साथ सुबह तीन बजे क्रिकेट मैच की कमेंटरी सुनने उठ जाती थी। फिर खेलों को लेकर बातें होती थी।

उन्होंने कहा कि पोर्टमोर स्कूल से बारहवीं की पढ़ाई करने के बाद ये तो लग गया था कि पढ़ाई होने वाली नहीं है। चूंकि मैं पहले से ही हैंडबाल व वालीवॉल खेलती थी। ऐसे में सोचा कि क्रिकेट खेला जाए। तो 2009 में एचपीसीए की धर्मशाला में रेजिडेंशियल अकादमी में दाखिला ले लिया।

सुषमा वर्मा ने कहा कि वो दो सालों से बाहर ही हैं। रेलवे में तैनात सुषमा वर्मा ने हिमाचल सरकार की ओर से उन्हें ऑफर की गई डीएसपी की पोस्ट की पेशकश पर कहा कि वो पहले से ही रेलवे में हैं व पांच साल का कांट्रेक्ट हैं। वो घर जाकर इस बावत अपने परिजनों से विमर्श कर फैसला करेंगी। वो बोली, वो अभी अपने घर सुन्नी नहीं पहुंची हैं।

नई प्रतिभाओं को सफलता के संदेश को लेकर उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसा कोई मंत्र तो नहीं है। वो बोली, 'एक बार रूटीन बन गया तो उसे किसी भी कीमत पर नहीं टूटने नहीं देना चाहिए। अगर सुबह योग करना हैं तो करना ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। शाम को नौ बजे सोना हैं तो सोना ही हैं। दृढ़ निश्चय व हार्डवर्क से संभव हैं। हार्डवर्क यानि क्वालिटी हार्डवर्क।

अब सुविधाओं की इतनी कमी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये जानकर उन्हें अच्छा लगा कि उनके बाद भी शिमला से कई खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। वो स्टेट के लिए खेलें, इंडिया के लिए खेलें ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो अंतराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में भारतीय टीम की ओर से खलेंगी। लेकिन वो आज टीम का हिस्सा हैं।

इस मौके पर जिला क्रिकेट एसोसिएशन ने उनके नाम से साल में बेस्ट क्रिकेटर के चयन के लिए सुषमा वर्मा रनिंग ट्राफी देने का एलान किया व कहा कि इसके साथ 11 हजार रुपए ईनाम भी दिया जाएगा। गुम्मा स्टेडियम में एक पैवेलियन का नाम भी सुषमा वर्मा के नाम पर रखा गया हैं। जिला शिमला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर, प्रेस सचिव मोहित सूद समेत एसोसिएशन के कई पदाधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे।

ठियोग में HRTC की बिल्डिंग ढही दो की मौत

शिमला/शैल। भारी बारिश की वजह से शिमला के समीप ठियोग में हिमाचल पथ परिवहन निगम के कार्यालय के ढह जाने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन के करीब लोगों के मलवे में फंसे होने का अदेशा हैं। सात .आठ घायलों को ठियोग के अस्पताल दाखिल कराया गया हैं जहां पर उनका इलाज किया जा रहा हैं। पांच घायलों को आईजीएमसी रेफर किया गया हैं। जिनमें से दो की स्थिति गंभीर बताई जा रही हैं।

हादसा सुबह हुआ है व तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। बिल्डिंग के मलवे में दोपहर तक भी आधा दर्जन के के करीब लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका हैं। सूत्रों के मुताबिक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई हैं व एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। परिवहन मंत्री जी एस बाली ने कहा कि घायलों के इलाज का सारा खर्च परिवहन विभाग उठाएगा।

मानसून सत्र में भाजपा के तेवरों पर निगाहें

शिमला/शैल। 22 अगस्त से शुरू हो रहे चार दिवसीय विधानसभा के मानसून सत्र में नडडा व धूमल धड़ों में बंटी भाजपा के तेवरों पर निगाह रहने वाली हैं। ये इस विधानसभा का आखिरी सत्र है और इस सत्र में आगामी विधानसभा चुनावों में दोनों पार्टियों की टोन क्या रहने वाली ये तय हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण सत्र 25 अगस्त तक चलेगा।

चूंकि इस बार भाजपा में सीएम के पद के दो-दो दावेदार हैं ऐसे में ये महत्वपूर्ण होगा कि बतौर नेता प्रतिपक्ष धूमल सदन में क्या रवैया अख्तियार करते हैं। अगर भाजपा उन्हें सीएम पद का प्रत्याशी घोषित कर देती तो वो कांग्रेस की ओर से सबसे बड़ी चुनौती सीएम वीरभद्र सिंह पर तीखा हमला करते। लेकिन वो एक अरसे से सीएम वीरभद्र को लेकर नरम पड़े हुए हैं।

चूंकि इस बार भाजपा ने नड्डा को मैदान में उतारने की अघोषित घोषणा कर रखी हैं तो धूमल भी चाहेंगे की अटैक भी नड्डा ही करें। वो इस नीति पर चल भी पड़े हैं। धूमल के नरम तेवरों को देखते हुए बीते दिनों पार्टी में उनसे हिसाब किताब पूरा करने की मंशा पाले वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने लीड ली और वीरभद्र सिंह पर हमला बोला। नड्डा भी सीएम को लेकर अग्रेसिव रह रहें हैं।

चूंकि मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार का मसला केंद्रीय एजेंसियों के सपुर्द हैं, ऐसे में सदन में इस मसले पर भी ज्यादा शोर-शराबा नहीं होता हैं।

लेकिन इस बार कानून-व्यवस्था को लेकर भाजपा के पास सरकार को घेरने का जबरदस्त मौका हैं। कोटखाई का गुडिया गैंगरेप व मर्डर का मामला हो या तीसा में तनाव। फारेस्ट गार्ड होशियार सिंह की रहस्यमयी मौत हो या तारा देवी में मिली बेहोश महिला की आइजीएमसी में मौत का मामला हो।

तिलकराज रिश्वत कांड से लेकर भ्रष्टाचार के दर्जनों मामलें हैं जिन पर सरकार की घेरेबंदी होनी हैं। लेकिन देखना यही हैं कि बतौर नेता प्रतिपक्ष धूमल क्या रुख अपनाते हैं। उनका रवैया महत्वपूर्ण होगा व आगामी चुनावों में वो क्या करने वाले हैं इसका भी संकेत मिल जाएगा। इससे भाजपा को अपनी रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।

देखना ये भी है कि नेता प्रतिपक्ष धूमल और बाकी भाजपा विधायक सदन में एका रखते हैं या बंटवारा नजर आता है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक जय राम ठाकुर, महेंद्र सिंह आदि अपना स्वतंत्र मत भी रखते हैं और ये सदन में झलकता भी रहा है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

नेता घोषित किये बिना घातक हो सकता है भाजपा का चुनाव लड़ना

शिमला/शैल। प्रदेश भाजपा जैसे-जैसे अपनी चुनावी तैयारीयों को बढ़ाती जा रही है उसी अनुपात में यह अटकलें भी लगातार तेज होती जा रही है कि भाजपा का अगला मुख्यन्त्री कौन होगा। बल्कि इस संबध में एक सर्वे भी सामने आया है जिसमें शान्ता कुमार, वीरभद्र सिंह, प्रेम कुमार धूमल, कौल सिंह ठाकुर, जेपी नड्डा, सुधीर शर्मा, जय राम ठाकुर और जीएस बाली के नाम शामिल किये गये हैं। इसमें शान्ता कुमार के लिये 11.5% वीरभद्र के लिये 18.5% प्रेम कुमार धूमल को 12% और और नड्डा को 31% लोगों की पंसद बताया गया है। इस कथित सर्वे में लोगों की राय में नड्डा 31% के साथ सबसे ऊपर और उनके बाद दूसरे स्थान पर 18.5% के साथ वीरभद्र है और धूमल 12% के साथ तीसरे स्थान पर है जबकि शान्ता कुमार 11.5% के साथ चौथे नम्बर पर है। शेष सब बहुत नीचे है इस सर्वे के मुताबिक प्रदेश के चुनाव वीरभद्र, धूमल और नड्डा तीन लोगों के गिर्द ही घूमेंगे।

इस समय भाजपा अपने को सत्ता का प्रबल दावेदार मानकर चल रही है बल्कि उसके कुछ नेता तो अभी से अधिकारियों /कर्मचारियों के साथ भावी मन्त्री के नाते व्यवहार कर रहे हैं। पिछले दिनों भाजपा की सपन्न हुई परिवर्तन यात्रा के दौरान जब मध्यप्रदेश के मुख्यमन्त्री ने नाहन-पांवटा आना था तब उनके लिये हैलीकॉप्टर को कहां लैण्ड करवाया जाये इसको लेकर राजीव बिन्दल संवद्ध अधिकारियों पर अपनी नाराजगी बड़े सख्त अन्दाज में व्यक्त कर चुके हैं जबकि वह प्रशासन पर एकदम नियमों के विरूद्ध अमल करने का दवाब बना रहे थे। भाजपा नेताओं के ऐसे व्यवहार से स्पष्ट हो जाता है कि यह लोग अभी से अपने को सत्ता में मानकर चल रहे हैं। स्वभाविक है कि जब नेता और कार्यकर्ता ऐसी मानसिकता के साथ व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से मुख्यमन्त्री कौन होगा की रेस में कई नाम जुड़ते चले जायेंगें। इस समय मुख्यमन्त्री के लिये प्रेम कुमार धूमल, जेपी नड्डा और अजय जम्वाल के नाम लम्बे अरसे से चर्चा में चल रहे हैं।

धूमल दो बार प्रदेश के मुख्यमन्त्री रह चुके हैं इसलिये उनका आकंलन उनके उस समय के काम के आधार पर होगा। वीरभद्र ने उनके कार्यकाल में कई कार्यो पर उनको घेरने का प्रयास किया है बल्कि इस प्रयास के तहत विजिलैन्स में कई मामलें भी दर्ज हुए लेकिन वीरभद्र सरकार को एक भी मामले में सफलता नही मिली है। बल्कि उल्टी फजीहत ही झेलनी पड़ी है। नड्डा-धूमल मन्त्रीमण्डल में एक बार स्वास्थ्य मन्त्री और एक बार वन मन्त्री रह चुके हैं। स्वास्थ्य मन्त्री के कार्यकाल में विभाग के निदेशक को जेल जाने तक की नौबत आ गयी थी तो वनमन्त्री के कार्यकाल में विभाग द्वारा प्रदेश से बाहर के एनजीओ को दिये गये करोड़ो के अनुदान पर उठे सवालों का जवाब आज तक नही आया है। इसी तरह कैट प्लान के पैसे से जेपी उद्योग ने आरनामैन्टस की खरीद कैसे कर ली थी यह रहस्य आज भी बना हुआ है। अब केन्द्र में स्वास्थ्य मन्त्री के कार्यकाल में एम्ज में मुख्य सतकर्ता अधिकारी रहे संजीव चतुर्वेदी के मामले में उठा विवाद अभी पूरी तरह थमा भी नही था कि यथावत ने एम्ज की जमीन के मामले को एक नयी चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया है। नड्डा के आकलन में यह सब कुछ सामने रहेगा ही यह तय है। संभवत: इसी सब कुछ को सामने रखते हुए भाजपा अध्यक्ष अमितशाह ने यह स्पष्ट कहा है कि भाजपा हिमाचल का चुनाव मुख्यमन्त्री का चेहरा सामने लाये बिना ही लड़ेगी।

भाजपा हाईकमान कई बार यह संकेत दे चुकी है कि वह चुनावों से पहले मुख्यमन्त्री का नाम उजागर नही करेगी। लेकिन इसके वाबजूद भाजपा के संभावित मुख्यमन्त्री चेहरों की सूची लम्बी ही होती जा रही है। अब इस सूची में अजय जम्वाल के बाद अनुपम खेर और सुषमा स्वराज जैसे नाम भी जोड़ दिये गये हैं। अपुनम खेर ने शिमला के टूटू में जमीन लेकर मकान बनवाने का काम शुरू कर रखा है और सुषमा स्वराज का तो धर्मशाला के धर्मकोट में होटल बना हुआ है। इन नामों के जुड़ने से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा में एक वर्ग बहुत ही योजनावद्ध तरीके से 'मुख्यमन्त्री कौन होगा' के सवाल को जिन्दा रखने की रणनीति अपनाए हुए है। मुख्यमन्त्री की रेस में इतने नामों के जुड़ने से कार्यकर्ता भी स्वभाविक रूप से इन सबसे परोक्ष/अपरोक्ष में अपनी-अपनी निकटता बनाने के लिये प्रयासरत हो गये हैं। ऐसे में सरकार और वीरभद्र के भ्रष्टाचार को जनता में ले जाने का काम कौन करेगा इसको लेकर अभी तक बहुत ज्यादा स्पष्टत: नही उभर सकी है क्योंकि अधिकांश नेताओं और कार्यकर्ताओं को इसकी विस्तृत जानकारी ही नही है।

आऊटसोर्स के हजारों कर्मचारियों का भविष्य अनिश्चितता में करोड़ों के घपले की भी आशंका

शिमला/शैल। वीरभद्र सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों /निकायों में आऊटसोर्स के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को लेकर एक पॉलिसी लाने की घोषणा एक लम्बे समय से करती आ रही है। बल्कि संवद्ध प्रशासन पर यह पॉलिसी लाने के लिये दवाब भी बनाया गया और जब इसे अधिकारियों ने एकदम नियमों के विरूद्ध

करार दिया तो कुछ अधिकारियों को इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा है इस समय सरकार में करीब 35000 कर्मचारी आऊटसोर्स के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह कर्मचारी एक ही कंपनी के माध्यम से रखे गये हैं। यह आरोप कर्मचारी नेता विनोद ठाकुर ने लगाया है। आरोप है कि इस कंपनी को सरकार 20% कमीशन दे रही है। 80% कर्मचारी को जाना है लेकिन यह 80% भी पहले इस कंपनी के खाते मे जाता है और फिर कंपनी अपने खाते से इनका भुगतान करती है इस तरह यह भी स्पष्ट नही है कि यह 80% भी कर्मचारी को वास्तव में ही मिल रहा है या नही।

आऊट सोर्स के नाम पर प्रदेश के श्रम विभाग के पास कितनी कंपनीयां पंजीकृत हैं और विभाग का उन पर किस तरह का कितना नियन्त्रण है इसको लेकर विभाग में कुछ भी स्पष्ट नही है। जिस कंपनी के माध्यम से हजारों कर्मचारी सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उस कंपनी का दफ्तर के नाम पर न्यू शिमला में एक छोटा सा बोर्ड टंगा है लेकिन दफ्तर में कितने कर्मचारी हैं इसको लेकर भी बहुत कुछ स्पष्ट नही है क्योंकि कंपनी में फोन करने पर कोई जानकरी नही मिल पाती है। इससे यह आशंका और पुख्ता हो जाती है कि इस कंपनी के नाम पर केवल एक तरह से लेवर सप्लाई का काम किया जा रहा है। क्योंकि आज तक इस कंपनी की ओर से ने तो किसी विज्ञापन के माध्यम से या न ही किसी रोजगार कार्यालय के माध्यम से यह सामने आ पाया है कि अमुक कार्यालय या कार्य के लिये उसे अमुक योग्यता के इतने व्यक्ति चाहिये। क्योंकि यदि कंपनी ऐसी प्रक्रिया अपनाती है तो वह रोजगार कार्यालय के समकक्ष हो जाती है और सरकार के मौजूदा नियम इसकी अनुमति नही देते हैं इससे हटकर यदि कंपनी ऐसी नियुक्तियों के लिये आमन्त्रण देती है तो उसे अपने ही कार्यालय में या उससे संवद्ध संस्थान में नियुक्ति देनी होगी। लेकिन इस कंपनी का अपना कोई ऐसा संस्थान है नही जहां पर यह किसी को नौकरी दे सके।

क्या सरकारी विभाग के आऊटसोर्स के माध्यम से किसी को दफ्तर में लिपिक या सहायक आदि की नौकरी दे सकते हैं ऐसा कोई प्रावधान भी नियमों में नही है ऐसे में आऊटसोर्स के माध्यम से केवल अस्थायी लेबर ही सप्लाई की जा सकती है और सरकारी दफ्तर में ऐसी लेबर रखने का भी प्रावधान नहीं है। इसी कारण से 20% कमीशन के बाद का 80% भी कंपनी के खाते में ही जमा करवाना पड़ता। क्योंकि यदि सरकार के दफ्तर की ओर से कर्मचारी को सीधे 80% का भुगतान कर दिया जाये तो यह लोग सीधे सरकारी कर्मचारी हो जाते हैं। इसी के साथ एक सवाल यह खड़ा होता है कि क्या यह कंपनी अपने रिकार्ड में इसके माध्यम से रखे गये कर्मचारियों को अपना रेगुलर कर्मचारी दिखाती है या नही। आज सरकारी कार्यालयों में इस कपंनी के माध्यम से रखे गये हजारों कर्मचारी इस उम्मीद में चल रहे हैं कि वह कभी नियमित हो जायेंगे। सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को लेकर पॉलिसी लाये जाने के वायदों से भी इन्हें यह उम्मीद बंधी थी जो कि एकदम आधारहीन थी।

आरोप है कि अभी सरकार ने आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिये विभागों को दस करोड़ रूपये जारी किये हैं। इसमें से दो करोड़ तो कंपनी को सीधे कमीशन के रूप में मिल जायेंगें शेष आठ करोड़ भी कंपनी के खाते में ही जमा होंगे और इसमें से वास्तव में ही संवद्ध कर्मचारियों को कितने मिलेंगे इसकी कोई जानकारी पैसे देने वाले विभाग को नही होगी। ऐसे में हजारों कर्मचारियों का भविष्य जहां अनिश्चितता में है वहीं पर इसमें करोड़ों का घपला होने की भी पूरी-पूरी संभावना बनी हुई है।

फिर उठी सोलन को नगर निगम बनाने की मांग-संघर्ष समिति हुई गठित

शिमला/शैल। सोलन हिमाचल का शिमला के बाद दूसरा बड़ा शहर है। 2011 की जनसंख्या गणना के मुताबिक शहर की आबादी उस समय 39256 जो बढ;कर 50,000 का आंकड़ा पा कर चुकी है। सोलन में 1950 में नगर परिषद का गठन हो गया था। 33.43 वर्ग किलो मीटर में फैले शहर को Mushroom city of India और city of RedGold के खिताब भी मिल चुके हैं। सोलन को नगर निगम बनाने का औपचारिक प्रस्ताव नगर परिषद बहुत पहले ही पारित करके सरकार को भेज चुकी है बल्कि इस प्रस्ताव पर जिलाधीश सोलन की ओर से 4-6-15 को कुछ स्पष्टीकरण भी मांगे गये थे। इन स्पष्टीकरणों का जवाब जिलाधीश और सचिव शहरी विकास विभाग को 8-7-15 को भेज दिया गया था। लेकिन सरकार की ओर से अब तक इस पर कोई कारवाई नही की गयी है। इस प्रस्ताव में शहर के साथ लगती 11208 जनसंख्या को भी शहर में मिलाने का प्रस्ताव दिया गया था। बल्कि इस मिलाये जाने वाले क्षेत्र में कोई कृषि योग्य भूमि भी नही आती है।

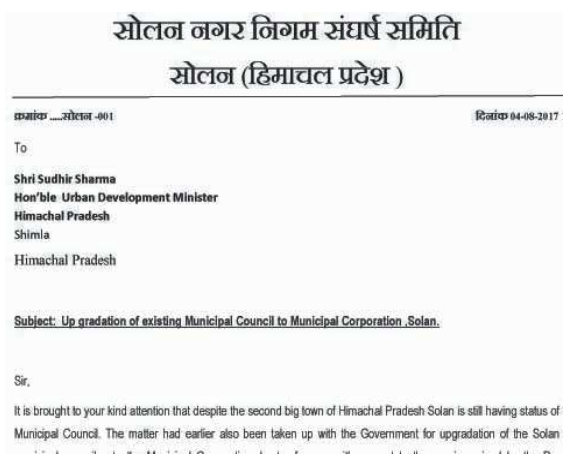

सोलन नगर निगम संघर्ष समिति
सोलन (हिमाचल प्रदेश)

क्रमांक .....सोलन -001 दिनांक 04-08-2017

To

Shri Sudhir Sharma
Hon'ble Urban Development Minister
Himachal Pradesh
Shimla
Himachal Pradesh

Subject: Up gradation of existing Municipal Council to Municipal Corporation ,Solan.

Sir,

It is brought to your kind attention that despite the second big town of Himachal Pradesh Solan is still having status of Municipal Council. The matter had earlier also been taken up with the Government for upgradation of the Solan

अब जब धर्मशाला को नगर निगम बना दिया गया है तब यहां के लोग इस मांग को लेकर बहुत सक्रिय हो गये हैं। लोगो ने नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष कुल राकेश पंत की अध्यक्षता में 10.7.17 को एक संघर्ष समिति का भी गठन कर लिया है। संधर्ष समिति ने 15.7.17 से 28.7.17 के बीच इसके लिये एक हस्ताक्षर अभियान भी छेड़ा था। जिसमें 7000 लोग इस प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर कर चुके है। आने वाले विधानसभा चुनावों की दृष्टि से सोलन के लोगों की इस मांग का जिले की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा यह तय है। इस समय सोलन जिले पांच विधानसभा क्षेत्रों में से चार पर भाजपा का कब्जा है केवल सोलन की सीट ही कांग्रेस के पास है जहां से कर्नल धनी राम शांडिल इस समय वीरभद्र मन्त्रीण्डल में मन्त्री हैं सोलन की इस मांग को स्वीकार करवाना शांडिल के राजनीतिक भविष्य के लिये भी महत्वपूर्ण होगा।